● वर्ष-6

● अंक-44

रायपुर, बुधवार
23 सितंबर 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> माताओं-बहनों का सम्मान...

महिला क्रिकेट में भारत ने जीता गोल्ड

एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका को 147 रनों के बड़े अंतर से हराया

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2026 में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुए एशियाई खेलों के क्रिकेट फ़ाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर यह मेडल हासिल किया। दिन की शुरुआत स्मृति मंधाना और शैफ़ाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ी की शानदार बल्लेबाज़ी से हुई। उन्होंने ओपनिंग में 99 रनों की साझेदारी की, जिसमें शैफ़ाली ने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद स्मृति ने मोर्चा संभाला और 45 गेंदों पर 79 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाईं, और ऐसे में स्मृति ने ही स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया।

पवेलियन लौटने के बाद, ऋचा घोष ने श्रीलंका के गेंदबाज़ों को हैरान कर दिया। सिलीगुड़ी में जन्मी इस खिलाड़ी ने मैच का रुख ही बदल दिया, जबकि श्रीलंका ने बीच के ओवरों में मैच को थोड़ा अपने पक्ष में कर लिया था। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने 22 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए, जिससे भारत ने पहली पारी में 216 रन का स्कोर खड़ा किया। यह एशियाई खेलों के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस बीच, स्मृति ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन भी पूरे कर लिए।

बल्ले से शानदार प्रदर्शन के बाद, शेफाली ने दूसरी पारी में गेंदबाज़ी में भी अपना दबदबा बनाए रखा। इस स्पिनर ने दो ओवर में सिर्फ़ तीन रन देकर दो विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा और श्री चरणी का प्रदर्शन भी उतना ही असरदार रहा। दोनों स्पिनरों ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि श्रेयंका पाटिल ने दो विकेट चटकाए। श्रीलंका की पूरी पारी कप्तान चमारी अथापथु पर टिकी थी, लेकिन फ़ाइनल मुकाबले में वह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं। इस अनुभवी ऑलराउंडर ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए, लेकिन पारी के सातवें ओवर में दीप्ति ने उन्हें आउट कर दिया। उनके आउट होने

के बाद, भारत की जीत बस कुछ ही समय की बात थी और ठीक वैसा ही हुआ।

पिछले कुछ सालों में, चमारी पर श्रीलंका की अत्यधिक निर्भरता ने उन्हें काफी नुकसान पहुँचाया है और भारत के खिलाफ़ फ़ाइनल में भी यही देखने को मिला। उनके अलावा, कोई भी खिलाड़ी 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका, जो उनकी बल्लेबाज़ी की क्षमता को दर्शाता है, खासकर ऐसे मैच में जहाँ टीम 217 रनों का पीछा कर रही थी। भारत के लिए यह जश्न मनाने की एक और रात है। उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और शानदार प्रदर्शन करते हुए उसे बरकरार रखा।

भारत में एफ-35 'स्टील्थ', राफेल का महाजमावड़ा

जोधपुर। राजस्थान का जोधपुर अगले कुछ दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य गतिविधियों में से एक का गवाह बनने जा रहा है। भारत की धरती पर अमेरिका का अत्याधुनिक एफ-35 'स्टील्थ' लड़ाकू विमान, फ्रांस का राफेल, संयुक्त अरब अमीरात का एफ-16 और बांग्लादेश का सी-130जे जैसे सैन्य विमान एक साथ आसमान में उतरने जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस, मिराज-2000, मिग-29 और जगुआर जैसे अग्रिम पंक्ति के विमानों के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी।

26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर होने वाला 'तरंग शक्ति-2026' केवल एक सामान्य हवाई अभ्यास नहीं है। यह ऐसा बहुराष्ट्रीय सैन्य मंच बनने जा रहा है, जहां दुनिया की अलग-अलग वायु सेनाएं एक साथ उड़ान भरेंगी, रणनीति साझा करेंगी और संयुक्त सामरिक अभियानों का अभ्यास करेंगी।

भारतीय वायुसेना के अनुसार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों की भागीदारी

होगी। इस अभ्यास का मकसद केवल आसमान में विमानों की ताकत दिखाना नहीं, बल्कि अलग-अलग वायु सेनाओं के बीच तालमेल, संयुक्त अभियान क्षमता और आधुनिक युद्धक परिस्थितियों में संचालन की क्षमता को मजबूत करना है।

सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिकी एफ-35 पर रहेंगी। पांचवीं पीढ़ी का यह स्टील्थ लड़ाकू विमान पहले 'एयरो इंडिया-2025' में भारत आ चुका है, लेकिन 'तरंग शक्ति' में इसकी भागीदारी इसे एक अलग स्तर का सैन्य महत्व देती है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में एफ-35 की पहली भागीदारी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

वंदे मातरम न गाने पर नहीं हो सजा

नई दिल्ली। वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह इस मामले में 1986 के अपने उस फैसले को ध्यान में रखे, जिसमें अंतरात्मा के आधार पर राष्ट्रगान गाने से इनकार करने वाले स्कूली बच्चों को संरक्षण दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। मामला कर्नाटक संगीत के गायक टीएम कृष्णा की याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2026 में संशोधित कानून के तहत वंदे मातरम के सभी छह अंतरों के गायन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत यह तय करने नहीं जा रही है कि राष्ट्रीय गीत क्या होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत के रूप में क्या तय किया जाए, यह राज्य के अधिकार क्षेत्र का विषय है। पीठ ने यह भी कहा कि अदालत राष्ट्रीय भावनाओं या वंदे मातरम से जुड़ी आकांक्षाओं पर फैसला देने के लिए नहीं बैठी है। उसका ध्यान इस बात पर रहेगा कि कानून के तहत 'कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता' के अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं। याचिका में वंदे मातरम के पूरे छह अंतरों को राष्ट्रीय गीत का आधिकारिक संस्करण मानने की व्यवस्था को भी चुनौती दी गई है।

टीएम कृष्णा ने कानून को दी है चुनौती

टीएम कृष्णा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 3 में 2026 में किए गए संशोधन और गृह मंत्रालय की 28 जनवरी तथा 9 जुलाई 2026 की ओर से जारी व्यवस्थाओं को चुनौती दी है। संशोधित धारा 3 के तहत राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगे किसी समूह में व्यवधान डालने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कृष्णा की याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय गीत के संबंध में दंडात्मक प्रावधानों का विस्तार और वंदे मातरम के सभी छह अंतरों के गायन से जुड़े निर्देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता से जुड़े संवैधानिक सवाल उठाते हैं।

मिशन 2027 के लिए भाजपा ने क्यों चुना गोरखपुर?

गोरखपुर। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत भाजपा ने गोरखपुर से की। प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का पहला गोरखपुर प्रवास महज संगठन की बैठक नहीं रहा। यह जमीन को पढ़ने की कवायद थी। तावड़े ने पहले सुना। फिर सवाल किए। एक के जवाबों को दूसरे से क्रॉस चेक किया। संगठन से लेकर समाज तक फीडबैक जुटाया। संकेत साफ रहा - पहले सुनो, फिर समझो और उसके बाद रणनीति बनाओ।

तावड़े ने जातीय जाल में उलझे गोरखपुर क्षेत्र को शायद इसलिए चुना क्योंकि भाजपा के मजबूत प्रभाव वाले इस इलाके में पिछले चुनावों में तस्वीर बदली है। 13 लोकसभा सीटों वाले क्षेत्र में भाजपा ने 2014 में 12 सीटें जीती थी। 2019 में यह संख्या 10 हुई और 2024 में छह रह गई। विधानसभा में भी 2017 की 49 सीटों की तुलना में 2022 में भाजपा 35 सीटों पर सिमट गई। यानी 2027 की चुनौती सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं है। पुराने गढ़ में बदले समीकरणों को समझने और उसके लिए रणनीति बनाकर पुरानी ताकत वापस हासिल करने की भी है। तावड़े ने अपने प्रवास की शुरुआत नई पीढ़ी से संवाद के साथ की। सहजनवां के अटल आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों से मिले।

करमा तिहार पर वित्त मंत्री चौधरी ने प्रदेशवासियों को दी गाड़ा-गाड़ा बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रकृति पूजा के पावन पर्व 'करमा तिहार' के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को गाड़ा-गाड़ा बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और स्वस्थ जीवन की कामना की है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि करमा तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्व प्रकृति के संरक्षण, भाईचारे, आपसी प्रेम और सामाजिक एकता का संदेश देता है। करम वृक्ष की पूजा कर प्रदेशवासी प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता और आस्था व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि करमा तिहार हमारी लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

सात नगर निगमों में छह जगह भाजपा प्रत्याशी की जीत

जयपुर/अजमेर। राजस्थान के सात नगर निगमों में मंगलवार को डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। अजमेर, उदयपुर, अलवर, पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर में मतदान के बाद नतीजे घोषित किए गए। इनमें छह नगर निगमों में भाजपा

के प्रत्याशी डिप्टी मेयर चुने गए, जबकि पाली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी महबूब टी ने जीत दर्ज की। अजमेर और पाली में मुकाबला बराबरी पर रहा, लेकिन दोनों जगह अलग-अलग प्रक्रिया से फैसला हुआ। अजमेर नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव बेहद करीबी रहा। भाजपा के हेमंत सांखला और कांग्रेस प्रत्याशी को 40-40 वोट मिले। बराबरी के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉटरी से फैसला किया गया, जिसमें भाजपा के हेमंत सांखला विजयी रहे। इससे पहले भाजपा की अनामिका शर्मा मेयर निर्वाचित हुई थीं। अजमेर के 80 वार्डों में कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद हैं।

अगले महीने से राज्यसभा में शून्य हो जाएगी बसपा

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अगले माह लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी हिस्सेदारी शून्य हो जाएगी। पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल अगले माह

समाप्त हो रहा है। बसपा के पास इतने विधायक नहीं हैं, जो उसके किसी उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकें। इन हालात में बसपा राज्यसभा चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारने का फैसला भी ले सकती है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद विधानसभा में भी बसपा की उपस्थिति समाप्त हो चुकी है। राज्यसभा में उनके किसी प्रत्याशी को जाने के लिए कम से कम 37 वोटों की दरकार होगी। इतनी बड़ी संख्या में वोट जुटा पाना फिलहाल बसपा के लिए असंभव है। इन हालात में पार्टी का लोकसभा, राज्यसभा के साथ यूपी की विधानसभा और विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं बचेगा। बीते करीब डेढ़ दशक से बसपा का सियासी सफर संकट भरा रहा है।

बैंक हड़ताल तय : 28 सितंबर से तीन दिन बंद रहेंगे बैंकं

नई दिल्ली। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 सितंबर से तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का एलान किया है। मंगलवार को उप मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष हुई सुलह बैठक बेनतीजा रही। यह हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर को होगी। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील की थी। इस एलान के बाद यह लगभग तय हो गया है कि बैंक अगले हफ्ते लगातार पांच दिनों तक बंद रहेंगे। 26 और 27 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। यूएफबीयू बैंकिंग कार्यबल के 90 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। इसकी मुख्य मांग 5-दिवसीय बैंकिंग है। अन्य मांगों में पेंशन में अद्यतन और सुधार शामिल हैं। वे सभी पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता सूत्र चाहते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में जाने का विकल्प भी उनकी मांगों में है। यदि हड़ताल होती है, तो 28 सितंबर से पहले सप्ताहांत की छुट्टी के कारण बैंकिंग सेवाएं पांच दिनों तक प्रभावित हो सकती हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर खुशी से झूमे अभिनेता

नई दिल्ली। गुजरात में नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद अभिनेता कार्तिक आर्यन ने खुशी और आभार जाहिर किया। उन्होंने इस पल को बेहद खास बताया। उन्हें फिल्म चंदू चैंपियन में बेहतरीन अदाकारी करने

के लिए यह अवॉर्ड मिला। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवॉर्ड लेते हुए वीडियो शेयर किया। इसके इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ग्वालियर के उस मम्माज बॉय को प्यार और मुस्कान के साथ याद कर रहा हूं, जिसने ऐसे माहौल में भी एक्टर बनने का सपना देखने की हिम्मत की, जहां लोग ऐसे सपनों पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार मैंने वह पल देखा और जिया। उत्साह और घबराहट से अभी भी सुन्न हूं। कार्तिक ने आगे लिखा एक छोटे शहर के लड़के का सपना। देश के हर एक्टर का सपना। बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड। 'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं। मैं कबीर सर और साजिद सर का हमेशा आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे बड़े पर्दे पर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड चैंपियन- मुरलीकांत पेटकर सर का किरदार निभाने की जिम्मेदारी सौंपी।

ओडिशा विधानसभा में हंगामा केवल 13 मिनट चला सदन

ओडिशा। ओडिशा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने संशोधित खनन कानून और स्कूली किताबों में गलतियों के मुद्दे पर नारेबाजी की। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। ओडिशा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने संशोधित खनन कानून और स्कूली बच्चों की नई पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर एक बजकर 10 मिनट तक और फिर शाम चार बजे तक के लिए स्थगित की गई जिसके बाद इसे दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। इस दौरान सदन में महज 13 मिनट ही कामकाज हो सका। सत्र की शुरुआत विधानसभा के छह पूर्व सदस्यों और नेपाल में आई भीषण बाढ़ एवं भूस्खलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके तुरंत बाद बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस के विधायक संसद में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम-2026 पारित किए जाने और स्कूली बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आसन के निकट आ गए।

आईआईटी में छात्र उस प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसने एक विद्यार्थी को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा था

बड़ा सवाल- क्या देश में जातिगत भेदभाव के आरोप का दुरुपयोग बढ़ रहा है?

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल में छात्रों का प्रदर्शन प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को लेकर हुआ था। वहीं मुंबई के आईआईटी में छात्र उस प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसने एक विद्यार्थी को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा था। यह विरोधाभास कई गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ओर परीक्षा की शुचिता और व्यवस्था की विफलताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया, तो दूसरी ओर एक विद्यार्थी की मौत के बाद संस्थागत जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या किसी छात्र को परीक्षा में अनुचित साधन इस्तेमाल करते हुए पकड़ना गलत है, या जांच पूरी होने से पहले उस घटना और उससे जुड़े आरोपों को सार्वजनिक करना गलत है?

उल्लेखनीय है कि आईआईटी-बंबई के बीटेक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी साहिल वाकोड़े की 18 सितंबर को मृत्यु के बाद परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जोकि एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है क्योंकि इसमें राजनीतिक स्वर भी शामिल हो गये हैं। हम आपको याद दिला दें कि संस्थान की शुरुआती सूचना में परीक्षा के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच (चैटजीपीटी) के कथित इस्तेमाल का उल्लेख किया गया था। छात्रों का आरोप था कि जिस विद्यार्थी की मृत्यु हो चुकी है, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ अनुशासनात्मक आरोप सार्वजनिक करना अनुचित था। बाद में आईआईटी-बंबई ने स्वयं अपनी पूर्व सूचना पर खेद जताते हुए कहा कि घटना से जुड़े तथ्य अभी जांच के अधीन हैं और जांच पूरी होने से पहले घटनाक्रम को इस तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं था। राजनीतिकखबरें पढ़ें

यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या किसी विद्यार्थी को नकल करते पकड़ना गलत है? इस प्रश्न का जवाब है नहीं। परीक्षा में नकल रोकना शिक्षक की जिम्मेदारी है। यदि किसी विद्यार्थी

के पास परीक्षा के दौरान अनुचित साधन पाए जाते हैं, तो संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होना स्वाभाविक है। आईआईटी-बंबई के शिक्षक मंच का भी कहना है कि संबंधित प्रोफेसर ने संस्थान की निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रिया के अनुसार अपना दायित्व निभाया। छात्रों के प्रतिनिधियों ने भी स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन नकल का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर है। लेकिन नकल पकड़ना और नकल का आरोप सिद्ध हो जाना दो अलग बातें हैं।

यही अंतर इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी शिक्षक को परीक्षा में अनुचित साधन रोकने का अधिकार है, लेकिन किसी आरोप को जांच पूरी होने से पहले अंतिम सत्य की तरह प्रस्तुत करना अलग प्रश्न है। आईआईटी-बंबई ने इसी बिंदु पर अपनी प्रारंभिक सूचना वापस ली और माना कि जांच पूरी होने से पहले घटनाओं का चरित्र-निर्धारण करना उचित नहीं था।

हम आपको बता दें कि छात्रों ने इस मामले में 18 मांगें रखीं हैं। इनमें प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को निलंबित करना, स्वतंत्र जांच समिति बनाना, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श व्यवस्था मजबूत करना, अनुशासनात्मक प्रक्रिया में सुधार, छात्र प्रतिनिधित्व बढ़ाना और जांच की समयसीमा तय करना शामिल है। छात्रों ने जांच के अंतरिम परिणाम के लिए 30 सितंबर और अंतिम रिपोर्ट के लिए 15 अक्टूबर की समयसीमा भी मांगी है। इसके बाद आईआईटी-बंबई ने प्रोफेसर डूला को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक अधिष्ठाता के पद से हटा दिया। हालांकि वह शिक्षक बने हुए हैं और छात्रों की मांग है कि उन्हें अध्यापन दायित्व से भी हटाया जाए।

मामला यहीं नहीं रुकता। साहिल के माता-पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में प्रोफेसर डूला पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर, आईआईटी-बंबई के शिक्षक मंच के अध्यक्ष राजकुमार पंत का दावा है कि संस्थान के अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ के पास साहिल की ओर से पिछले तीन-चार महीनों में ऐसी कोई शिकायत दर्ज होने का रिकॉर्ड नहीं है। शिक्षक मंच ने डूला के समर्थन में कहा है कि उन्होंने संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया।

वायरल वीडियो विवाद पहुंचा कोर्ट

अजय चंद्राकर ने सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ किया मानहानि का दावा

धमतरी। वायरल वीडियो को लेकर चल रहा सियासी विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और लोकगायिका व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। मामला स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है।

चंद्राकर का आरोप है कि भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बनाया गया पुराना वीडियो स्वतंत्रता दिवस का बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। उनका कहना है कि इस तरह वीडियो प्रसारित किए जाने से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर उन्होंने दोनों के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है।

वायरल वीडियो मामले में धमतरी पुलिस ने अलग कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कुरूद स्थित भाजपा कार्यालय में 22 मार्च 2026 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाजपा का झंडा फहराए जाने का वीडियो बनाया गया था। आरोप है कि बाद में इसी मूल वीडियो को डाउनलोड कर एडिट किया गया और उसे स्वतंत्रता दिवस से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। पुलिस ने भुनेश्वर निराला (25) और राकेश निराला (35) को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया। दोनों सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम जिल्दी के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस का दावा है कि वीडियो एडिट करने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं।

स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर अजय चंद्राकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे भाजपा का झंडा फहराते नजर आ रहे थे। वीडियो को इस दावे के साथ प्रसारित किया गया कि 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराया। बाद की पड़ताल में पुलिस के अनुसार यह वीडियो 15 अगस्त 2026 का नहीं, बल्कि पहले के भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का था।

इसी वीडियो को लेकर रायपुर के सिविल लाइन थाने में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी स्न्ढ्ढक्र दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 336(4), 353(2) और 196 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

अब अजय चंद्राकर की ओर से दायर मानहानि याचिका के बाद विवाद का एक और पहलू अदालत पहुंच गया है। मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही और दोनों पक्षों की दलीलों पर नजर रहेगी।

लंका पहाड़ी के जंगल में माओवादी डंप बरामद

बीजापुर। माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। थाना बेदरे क्षेत्र के लंका गांव की पहाड़ी के जंगल में सर्चिंग और डिमाइनिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए माओवादी डंप का पता लगाया।माओवादी डंप से बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई है।सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में लगातार सर्चिंग और डिमाइनिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान जंगल में संदिग्ध स्थान की जांच करने पर जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए डंप का पता चला। बीजापुर में लगातार सर्चिंग और डिमाइनिंग की जा रही है। इसी कड़ी में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।SLR/LMG रायफल एक, INSAS रायफल एक , ।315 बोर बंदूक एक, BGL लॉन्चर दो, BGL सेल 17, चाइना हैंड ग्रेनेड एक, SLR के 49 जिंदा राउंड, ।315 बोर के 15 राउंड, BGL कारतूस 15, स्न्क्र की चार मैगजीन, 315 बोर की एक मैगजीन सहित अन्य सामग्री एवं उपकरण, पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने बरामद हथियार और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया है। डंप को लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई और उससे जुड़े लोगों की पतासाजी की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। बीजापुर जिले में सितंबर माह के

दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में माओवादियों द्वारा पूर्व से छिपाकर रखे गए कई डंप बरामद किए जा चुके हैं। 20 सितंबर 2026= थाना भैरमगढ़ क्षेत्र के आदवाड़ा जंगल से AK-47, ।315 बोर हथियार, सिंगल शॉट पिस्टल सहित जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद किए गए। 16 सितंबर 2026= थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के बड़े आलवाड़ा जंगल से ।315 बोर रायफल, 49 जिंदा राउंड, ।303 के 25 जिंदा राउंड और 12 बोर के 49 जिंदा राउंड के साथ करीब 8 किलोग्राम जिलेटिन, वॉकी-टॉकी एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए । 10 सितंबर 2026= थाना मिरतुर क्षेत्र के इंडरीपाल जंगल से अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गए नॉन इलेक्ट्रिकल वायर के सात बंडल, डेटोनेटर और ग्रेनेड बरामद हुए।1 सितंबर 2026= थाना भोपालपटनम क्षेत्र के नीलमड़गु जंगल से माओवादी डंप से 12 बोर का देशी कट्टा, क्चञ्जरुलॉन्चर, आठ क्चञ्जरुसेल, 12 बोर के 10 जिंदा राउंड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई।

लगातार हो रही कार्रवाइयों से सुरक्षा बलों द्वारा जंगल क्षेत्रों में चलाए जा रहे सर्चिंग और डिमाइनिंग अभियान की सक्रियता सामने आ रही है। लंका पहाड़ी में हुई ताजा कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में निगरानी और सर्चिंग को और मजबूत किया है।

बीजापुर पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि क्षेत्र में कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री दिखाई देती है तो जल्द से जल्द पुलिस को इसकी सूचना दें

कांग्रेस की राष्ट्रय संयुक्त सचिव प्रीति मांझी के खिलाफ एफआईआर

गौरेला पेंड्रा मरवाही। भारतीय युवा कांग्रेस की राष्टीय संयुक्त सचिव एवं झारखंड की सह-प्रभारी प्रीति मांझी समेत उनके माता पिता के खिलाफ गौरेला थाने में मामला दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत लालपुर के सचिव अंजनी कुमार यादव ने महतारी सदन के प्रस्तावित निर्माण कार्य को रोकने और पंचायत प्रतिनिधियों और शासकीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने को लेकर शिकायत दी है।शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0416/26 दर्ज किया है। पुलिस ने प्रीति मांझी और उनके परिवार के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 296, 3(5) एवं 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपियों में कलीराम मांझी,उनकी बेटी प्रीति मांझी और कलीराम मांझी की पत्नी शामिल हैं। पंचायत सचिव की शिकायत के मुताबिक लालपुर ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ शासन की महतारी सदन योजना के तहत करीब 30

लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण स्वीकृत हुआ है। इसके लिए खसरा नंबर 6/1 एवं 8/1 की भूमि का चयन किया गया था।लेकिन निर्माण कार्य को रुकवाने की कोशिश की गई।

शिकायत के मुताबिक 3 सितंबर 2026 को रेलवे स्टेशन काली मंदिर के पास प्रस्तावित निर्माण स्थल पर ले-आउट से पहले सफाई का काम हो रहा था।इसी दौरान तीनों आरोपी मौके पर पहुंचे और शासकीय कार्य को रुकवाने लगे। पंचायत की ओर से इस संबंध में 12 सितंबर को गौरेला थाने में शिकायत किए जाने की बात भी आवेदन में कही गई है।

इसके बाद 19 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे इंजीनियर द्वारा निर्माण स्थल पर ले-आउट कराया जा रहा था। शिकायत के अनुसार इसी दौरान तीनों आरोपी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य शुरू नहीं करने देने की बात कहते हुए पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों से कथित रूप से गाली-गलौज की।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई और निर्माण कार्य बंद करा दिया गया।

पंचायत सचिव के आवेदन में राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए बताया गया है कि खसरा नंबर 6/1 का रकबा 10।246 हेक्टेयर है और यह भूमि छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज है। आवेदन के अनुसार 8 सितंबर 2026 को राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी ने स्थल निरीक्षण कर पंचनामा और जांच प्रतिवेदन तैयार किया था। शिकायत में दावा किया गया है कि जांच के दौरान संबंधित भूमि पर आरोपित पक्ष का वैध हक अथवा कब्जा नहीं

बलरामपुर रामानुजगंज औषधि विक्रेता संघ की नई कार्यकारिणी का गठन

बलरामपुर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में औषधि विक्रेता संघ के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। बलरामपुर जिले के औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 14 सितंबर को संघ का निर्वाचन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पर अजय गुप्ता, सचिव पद पर द्वारिका नाथ पांडेय और कोषाध्यक्ष पद पर नवीन गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आमसभा और शपथ ग्रहण के बाद जिले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बलरामपुर रामानुजगंज जिला के औषधि विक्रेता संघ की चतुर्थ आमसभा और कार्यकारिणी का गठन हुआ है। बलरामपुर जिले के औषधि विक्रेता संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि वे पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि केमिस्ट नशे का व्यापार नहीं करते हैं, इसलिए बिना वजह उनकी दुकानों पर पुलिस नहीं भेजी जानी चाहिए। हालांकि, किसी केमिस्ट को लेकर पुलिस को संदेह हो तो संघ के सभी पदाधिकारी जांच और कार्रवाई में सहयोग करेंगे। बलरामपुर रामानुजगंज औषधि विक्रेता संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के चुनाव में जिले के सभी 238 केमिस्टों के द्वारा उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अब संगठन में बेहतर कार्य करने, परस्पर आपसी सहयोग और संगठन को मजबूत बनाने की योजना है।

मजदूर, चायवाले और इलेक्ट्रिशियन के नाम फर्जी फर्में, म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों का कारोबार

दुर्ग। म्यूल अकाउंट्स नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई ने बड़ा आंकड़ा सामने रखा है। 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध स्न्ढ्ढक्र रिकॉर्ड के मुताबिक जिले में म्यूल अकाउंट से जुड़े 63 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों की जांच में 1668 बैंक खातों का पता चला है। रिकॉर्ड के अनुसार 227 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 30 एजेंट भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं। यानी गिरफ्तारी और एजेंटों को मिलाकर यह संख्या 257 तक पहुंचती है।

इन मामलों में दुर्ग जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के साथ कई बैंकों के खाते शामिल हैं। सबसे ज्यादा खातों वाले मामलों में सुपेला थाना क्षेत्र का Bandhan Bank केस शामिल है, जिसमें 172 खाते दर्ज हैं। छावनी के IDBI Bank मामले में 171 खाते, पुरानी भिलाई के Bank of Maharashtra केस में 164 खाते, भिलाई नगर के PNB मामले में 130 खाते और भिलाई भट्ठी के SBI मामले में 108 खातों का रिकॉर्ड सामने आया है।दुर्ग थाना क्षेत्र के Indian Overseas Bank मामले में भी 106 खाते जांच के दायरे में हैं। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होता है और इसका इस्तेमाल गैर कानूनी काम करने के लिए किया जाता है। खाताधारकों को कमीशन या आसान कमाई का लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल किए जाते हैं।अब इस पूरे मामले में रायपुर में सामने आया कथित फर्जी फर्म और ढ्ढञ्जष्ट से जुड़ा प्रकरण भी जांच के लिहाज से चर्चा में है। हालांकि अभी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर रायपुर के मामले को दुर्ग के 63 स्न्ढ्ढक्र और 1668 म्यूल अकाउंट से सीधे जोड़ने का कोई पुष्ट आधार सामने नहीं आया है। रायपुर के लभांडी इलाके में त्रस्ज्ञ विभाग की जांच के बाद मेसर्स एम। अगस्त्य इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर अमन कुमार अग्रवाल के खिलाफ तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

दुर्ग के म्यूल अकाउंट मामलों और रायपुर के कथित फर्जी फर्म मामले के बीच फिलहाल कोई सीधा कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ है।दोनों मामलों को जोड़ने के लिए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, चड्ढष्ट दस्तावेजों और पैसों के ट्रांजेक्शन का मिलान जरूरी होगा। अगर जांच में कोई समान बैंक खाता, मोबाइल नंबर, चड्ढष्ट दस्तावेज या रकम के ट्रांजेक्शन की कड़ी सामने आती है, तभी दोनों मामलों के बीच संभावित संबंध पर आगे निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पनीर पर बड़ा सवाललेकिन लैब रिपोर्ट में सैंपल अमानक

जगदलपुर। आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छी-खासी कीमत चुकाकर थाली ऑर्डर करते हैं और भरोसा करते हैं कि आपकी प्लेट में परोसा जा रहा खाना सुरक्षित होगा। लेकिन जगदलपुर में सामने आई पनीर की लैब रिपोर्ट ने इसी भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। शहर के अलग-अलग होटल और रेस्टोरेंट से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट सामने आई तो तीन जगहों के पनीर निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं एक होटल से लिए गए पनीर के सैंपल को सीधे तौर पर असुरक्षित घोषित किया गया है। जांच में न्यू महावीर थाली, मितहरा रेस्टोरेंट और गंगा गोल्ड कंपनी के पैक्ड पनीर के सैंपल अमानक पाए गए हैं। यानी ये पनीर तय गुणवत्ता मानकों पर फेल हुए हैं। सबसे गंभीर रिपोर्ट होटल लक्ष्मण एवेन्यू के पनीर की है, जिसे लैब ने असुरक्षित बताया है। विभाग के मुताबिक ऐसे पनीर का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। खास बात यह है कि जांच में सामने आया पनीर सिर्फ किसी एक तरह के कारोबार से जुड़ा नहीं है।

सड़क पर वायरल होने के बाद 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। गौरेला के ?अमरकंटक चौक के पास बीच सड़क जन्मदिन मनाने और ट्रैफिक बाधित करने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। भाजयुमो अध्यक्ष समेत तीन नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। जानकारी के मुताबिक, घटना 18 सितंबर की है। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ दुबे 'सिद्धू' का जन्मदिन अमरकंटर चौक के पास बीच सड़क पर सेलिब्रेट किया गया। इसके लिए बकायदा मंच भी तैयार किया गया था। ढोल-ताशे के साथ शोर और लोगों की भीड़ के बीच यातायात बाधित रहा। कार और बाइक चालकों को जाम का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भाजुयमो के जन्मदिन मनाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आयोजनकर्ता सहित अन्य लोगों की पहचान कर एफआईआर दर्ज की।

सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी संपत्ति पर आयकर विभाग की कार्रवाई

दुर्ग भिलाई। कोल लेवी घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी भिलाई के जुनवानी स्थित ए-1 सूर्या रेजिडेंसी की एक संपत्ति पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है।विभाग की टीम ने करीब 200 वर्गमीटर में फैले मकान को सील कर अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ तहसीलदार और पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आयकर विभाग ने इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए सील किया है। मकान में पहले मनीष उपाध्याय रह रहे थे। विभाग की ओर से पहले उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद मकान को खाली करा लिया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयकर विभाग की टीम संपत्ति को सील करने पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर प्रॉपर्टी सील करने की मुनादी भी कराई गई। टीम ने मकान को विधिवत सील करने के बाद संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया।

मां दंतेश्वरी मंदिर की 11 दान-पेटियों से 21.62 लाख नगद मिले

दंतेवाड़ा। मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा की दान पेटियां 07 महीने 24 दिन बाद शारदीय नवरात्र से पहले मंगलवार को मंदिर की कुल 11 दान पेटियां खोली गईं। इनसे 21 लाख 62 हजार 331 रुपए नगद मिले। इसके अलावा सोने-चांदी के आभूषण और भक्तों के मन्नत के पत्र भी मिले हैं। दान पेटियों से मिले आभूषणों और अन्य सामग्री को सुरक्षित रखा गया है। भक्तों ने नौकरी, संतान प्राप्ति सहित अलग-अलग मन्नतों को लेकर मां दंतेश्वरी के नाम पत्र पेटियों में डाले थे। इन पत्रों को भी पेटियां खोलने के दौरान निकाला गया, इस दौरान भक्तों की निजता का ध्यान रखा गया है।मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटियां इससे पहले 28 जनवरी 2026 को खोली गई थीं। उस समय पेटियों से 19 लाख 44 हजार 448 रुपए नगद मिले थे। इस बार पिछली बार की तुलना में 2 लाख 17 हजार 883 रुपए ज्यादा मिले हैं। साल में दो बार दानपेटी खोली जाती है। शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, न्यू ईयर, और फागुन मेला के समय मंदिर में भक्तों की ज्यादा भीड़ होती है।

राजनांदगांव से मंडला-जबलपुर नई रेल लाइन की मांग तेज

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को सीधे रेल नेटवर्क से जोडऩे की दिशा में राजनांदगांव-खैरागढ़-कवर्धा-मंडला-जबलपुर नई रेल लाइन की मांग को लेकर महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। नागपुर में आयोजित सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने इस बहुप्रतीक्षित रेल लाइन का प्रस्ताव प्रमुखता से रखा। प्रस्ताव के सामने आने से राजनांदगांव सहित आसपास के क्षेत्रों में इस रेल परियोजना को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।बैठक में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया कि राजनांदगांव को खैरागढ़, कवर्धा, मंडला होते हुए जबलपुर से जोडऩे वाली नई रेल लाइन से छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। इससे राजनांदगांव और जबलपुर जैसी दोनों संस्कारधानियों के साथ मंडला क्षेत्र भी रेल नेटवर्क से बेहतर ढंग से जुड़ सकेगा।प्रस्तावित रेल मार्ग से मंडला एवं आसपास के आदिवासी अंचलों, कान्हा क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होने की संभावना है।

पांच हफ्ते की मजदूरी के लिए घिस गई चप्पल, फिर भी नहीं मिला मेहनत का हक

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के मजदूर अपनी मेहनत की मजदूरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने को मजबूर हैं। मजदूरी की आस में बैगा मजदूरों को पंचायत से लेकर अधिकारियों के कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय तक कई बार चक्कर लगाना पड़ा।

ग्रामीणों के मुताबिक स्टॉपडैम निर्माण को पूरा हुए करीब एक साल बीत चुका है, लेकिन कुछ मजदूर अब भी अपने मेहनताने का इंतजार कर रहे हैं। विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत चुटकी की आबादी करीब 526 है। यहां बैगा समुदाय के लोग भी निवास करते हैं। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने स्टॉपडैम निर्माण में मजदूरी की। काम के दौरान उनकी हाजिरी मस्टररोल में दर्ज की गई और निर्माण कार्य से संबंधित फोटो भी लिए गए। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है।

जगबतिया बैगा बताती है कि उन्होंने और गांव के कई लोगों ने स्टॉप डैम निर्माण कार्य में मजदूरी की थी, लेकिन आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। अपनी शिकायत लेकर पैसे खर्च कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां

भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा आवेदन भी वापस कर दिया गया और जनकपुर जाने को कहा गया। जब जनकपुर में भी कोई सुनवाई नहीं करता, तो हम अपनी फरियाद लेकर आखिर कहां जाएं? स्टॉप डैम का पैसा नहीं मिल रहा है। हम परेशान है। अपने पैसे खर्च कर गए थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अधिकारी बनने का क्या मतलब जब हमारी परेशानी ही नहीं सुन रहे। धूप में पानी पी पीकर काम किए लेकिन पैसा नहीं दिए-जगबतिया बैगा, स्थानीय भगवती बैगा ने बताया कि वाटरशेड के माध्यम से स्टॉप डैम निर्माण कार्य में हमने मजदूरी की थी। अपनी समस्या को लेकर सभी ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय भी गए और आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। साल बीत गया है, स्टॉप डैम का भुगतान नहीं किया है। परिवार कैसे चलाए। कलेक्टर ऑफिस जाकर आवेदन भी दिए लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया गया। 5 हफ्ते काम किए थे-भगवंती बैगा, स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि स्टॉपडैम निर्माण को पूरा हुए करीब एक साल हो चुका है। भुगतान के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन अब तक सभी मजदूरों को भुगतान नहीं मिल सका है। स्टॉप डैम का पैसा एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं मिला है। अपनी समस्या को लेकर हम सभी ग्रामवासी मनेंद्रगढ़ कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन वहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई-सरस्वती बैगा

वाटरशेड के तहत स्टॉप डैम निर्माण कार्य में हम लोगों ने मजदूरी की थी, लेकिन पांच सप्ताह की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। अपनी शिकायत लेकर हम सभी ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय भी गए थे और आवेदन दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक हमारी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है-मीरा बाई बैगा

30 दिन, 30 सेवा कार्य संकल्पः 17वें दिन रायगढ़ में साइबर जागरूकता अभियान

रायगढ़। सेवा संकल्प 30 दिन, 30 सेवा कार्य के 17वें दिन शनिवार को सुश्री अलीशा अंसारी के नेतृत्व में रायगढ़ शहर के विभिन्न स्थानों पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।

आज के डिजिटल युग में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड, ठगी और साइबर अपराधों को देखते हुए इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और दुकानदारों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। सुश्री अलीशा अंसारी की टीम ने शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड और चौक सहित कई

जगहों पर जाकर लोगों से संवाद किया। ओटीपी और यूपीआई से ठगी से बचाव - किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड और बैंक डिटेल्स साझा न करें। फेक लिंक और लॉटरी के झांसे से सावधान - आपने इनाम जीता है जैसे मैसेज वाले लिंक पर क्लिक न करें। सोशल मीडिया सुरक्षा - अपनी निजी फोटो और जानकारी अनजान लोगों से शेयर न करें, टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें। हेल्पलाइन की जानकारी - साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या http://cyber-crime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। इस मौके पर सुश्री अलीशा अंसारी ने कहा, जैसे हम घर में ताला लगाकर सुरक्षा करते हैं, वैसे ही मोबाइल और इंटरनेट पर भी डिजिटल ताला लगाना जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही से हमारी मेहनत की कमाई जा सकती है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की।

संक्षिप्त समाचार

इलाज के बाद आज छत्तीसगढ़ लौट रहे किरण देव, संभालेंगे भाजपा की कमान

रायपुर। सड़क हादसे में घायल छत्तीसगढ़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दिल्ली में उपचार के बाद आज छत्तीसगढ़ लौटेंगे। वे दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ निवास से रवाना होकर शाम तक रायपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। किरण सिंह देव लौटते ही प्रदेश में भाजपा की कमान फिर से संभालेंगे। बता दें कि किरण सिंह देव 29 जुलाई को परिवार के साथ बागेश्वर धाम से लौट रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट क्षेत्र में झांसी-ललितपुर नेशनल हाईवे-44 पर उनकी इनोवा आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई थी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाया गया, जहां मेदांता अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया। हादसे के बाद से उनका उपचार दिल्ली में ही चल रहा था। अब उपचार पूरा होने के बाद वे वापस छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। इलाज के दौरान दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ निवास में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने किरण सिंह देव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में आयोग का भ्रमण

रायपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की जमीनी स्थिति जानने के लिए चार जिलों के दौरे पर है। 20 से 25 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे में रायपुर, सक्ती, जशपुर और कांकेर में जनजातीय आवासीय छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण, ग्राम भ्रमण और समुदाय के लोगों से सीधे संवाद किया जा रहा है। आयोग की टीम विशेष रूप से नागवंशी, संसारी उरांव, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा समुदायों से जुड़े क्षेत्रों में पहुंचकर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त करेगी। जशपुर में 22 और 23 सितंबर को विशेष रूप से जनजातीय ग्रामों का भ्रमण निर्धारित है। कांकेर में 24 सितंबर को जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण को लेकर संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें पंचायत एवं जिला स्तर की महिला जनप्रतिनिधियां शामिल होंगी। 25 सितंबर को रायपुर में आयोग में लंबित प्रकरणों को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं प्राधिकारियों के साथ बैठक होगी। आयोग की ओर से संबंधित अधिकारियों को जांच दल को आवश्यक सहयोग, दस्तावेज उपलब्ध कराने और मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दपूमरे से चलने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदलाव

बिलासपुर। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में रेल लाइन से जुड़े निर्माण कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। ट्रेन नंबर 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को बिलासपुर से रवाना नहीं होगी। दोनों तिथियों की यात्रा रद्द रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस 26 सितंबर और 3 अक्टूबर 2026 को बक्सर से रद्द रहेगी। 17007 चेरलापल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस: 26 और 29 सितंबर को चेरलापल्ली से रवाना होकर किऊल-मुंगेर-बरौनी के रास्ते दरभंगा जाएगी। 17008 दरभंगा-चेरलापल्ली एक्सप्रेस: 25 और 29 सितंबर तथा 2 अक्टूबर को दरभंगा से रवाना होकर मुंगेर-किऊल के परिवर्तित मार्ग से चेरलापल्ली जाएगी। 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस: 24 सितंबर और 1 अक्टूबर को हैदराबाद से रवाना होकर किऊल-मुंगेर-बरौनी के रास्ते रक्सौल जाएगी। इसके अलावा 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस: 27 सितंबर और 4 अक्टूबर को रक्सौल से रवाना होकर मुंगेर-किऊल के परिवर्तित मार्ग से हैदराबाद जाएगी।

दुर्ग जिले के विभिन्न सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 40.85 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़-शासन जल संसाधन विभाग द्वारा दुर्ग जिले विभिन्न सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 40 करोड़ 85 लाख 2 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में दुर्ग जिले के सुरपा व्यपवर्तन योजना का जीर्णोद्धार एवं नहर प्रणाली का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य के लिए दो करोड़ 23 लाख 56 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 121 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाइ सुविधा मिलेगी। इसी तरह से मोहंदी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहरों का लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 96 लाख 55 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। तिरगा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख 26 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 107 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। गनियारी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख 26 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 254 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। रिसाली उमरपोटी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 97 लाख 94 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 162 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

पीएम मोदी के 25 वर्ष के सेवा संकल्प को साकार करने शहर में 25 से पदयात्रा सप्ताह

- मुख्यमंत्री साय करेंगे शुभारंभ, राज्यपाल रमेन डेका की उपस्थिति में 2 अक्टूबर को होगा भव्य समापन

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा संकल्प को साकार करने तथा जनसेवा और जनजागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरन्दर मिश्रा के नेतृत्व में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पदयात्रा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आठ दिनों तक चलने वाले इस अभियान में नशामुक्ति, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और जनसमस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने जैसे विषयों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक

आयोजित होने वाला यह अभियान सेवा, संकल्प और जनभागीदारी की भावना को समर्पित रहेगा।

विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि पदयात्रा उनके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसेवा और जनजागरण का निरंतर संकल्प है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गृह ग्राम सराईपाली दुर्गापाली से पदयात्रा की शुरुआत की थी और पिछले 27 वर्षों से लगातार पदयात्रा के माध्यम से समाज में जनजागरूकता का संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से लोगों से सीधे संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं को समझना और समाजहित के विषयों पर जागरूकता पैदा करना उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण उनके लंबे जनजागरण अभियान का प्रमुख संकल्प रहा है। उनके अनुसार पिछले 26 वर्षों के दौरान लगातार चलाए गए जनजागरूकता प्रयासों के माध्यम से 22,640 लोगों को नशामुक्ति की दिशा में प्रेरित करने का कार्य किया गया है।

उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार और समाज के भविष्य पर भी असर डालता है। इसलिए पदयात्रा सप्ताह के दौरान नशामुक्ति के संदेश को विशेष रूप से जन-जन तक पहुंचाया जाएगा और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पदयात्रा सप्ताह का शुभारंभ 25 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा, तेलीबांधा थाना चौक में माल्यार्पण के साथ होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, पूर्व राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा श्रीमती विभा अवस्थी सहित निगम-मंडल एवं आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य, संगठन के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, साधु-संत एवं युवा नेतृत्व की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। माल्यार्पण के पश्चात विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा के नेतृत्व में पदयात्रा प्रारंभ होगी। पदयात्रा तेलीबांधा होते हुए शहीद भगत सिंह चौक, गौरव पथ पहुंचेगी, जहां प्रथम दिवस का समापन होगा। इस दौरान रविग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जाएगा।

खेल अकादमियों में प्रवेश का मौका

23-24 सितंबर को रायपुर में होगा चयन ट्रायल

रायपुर। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने रायपुर जिले में संचालित गैर-आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश और प्रवेश के नवीनीकरण के लिए 23 और 24 सितम्बर को चयन ट्रायल का आयोजन किया है। इसमें भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी 23 सितम्बर को रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए आधार कॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के उल्लेख वाली प्रमाणित अंकसूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गैर-आवासीय बालक-बालिका तीरंदाजी और बालिकाओं के फुटबॉल (बालिका) के लिए चयन ट्रायल 23 सितम्बर को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा तथा तीरंदाजी एरिना (बालिका खेल छात्रावास के सामने) में होंगे। वहीं गैर-आवासीय बालक-बालिका हॉकी एवं बालक-बालिका एथलेटिक्स के लिए चयन ट्रायल 24 सितम्बर को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा एवं हॉकी स्टेडियम पिच-02 में सुबह 7 बजे से आयोजित किए गए हैं। चयन ट्रायल में राज्य के बालक-बालिका खिलाड़ी तथा अन्य राज्यों के 13 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। फुटबॉल एवं तीरंदाजी खिलाड़ियों का 23 सितम्बर को पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं खेल कौशल परीक्षण स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा एवं तीरंदाजी एरिना रायपुर में किया जाएगा।

मंत्री राजवाड़े की पहल से भटगांव विस के 7 धान उपार्जन केंद्र होंगे सुविधा-संपन्न

पक्के फड़ एवं समतलीकरण कार्य को मिली स्वीकृति

रायपुर। किसानों को धान उपार्जन के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भटगांव विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। भटगांव विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के 7 धान उपार्जन केंद्रों में पक्के फड़ निर्माण एवं समतलीकरण कार्य के लिए 69.58 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इससे इन केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और किसानों को धान बेचने के दौरान अधिक व्यवस्थित एवं सुविधाजनक वातावरण मिलेगा।

स्वीकृत कार्यों में सूरजपुर विकासखंड के टमकी, सिरसी, करोटी बी, खोपो, बतरा,

सांवारांवां एवं कुर्रीडीह स्थित धान उपार्जन केंद्र शामिल हैं। प्रत्येक केंद्र में 9.94 लाख रुपए की लागत से पक्के फड़ निर्माण एवं समतलीकरण का कार्य किया जाएगा। धान उपार्जन केंद्रों में पक्के फड़ और समतलीकरण होने से उपार्जन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी। इससे धान की आवक, खरीदी और रख-रखाव के दौरान होने वाली व्यावहारिक परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को उपार्जन केंद्रों पर बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र में अधोसंरचना विकास को गति देने के क्रम में यह स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा भटगांव विधानसभा क्षेत्र में किसानों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के प्रयासों का यह एक और परिणाम है। इससे धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था मजबूत होने के साथ किसानों को सुविधाजनक उपार्जन व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

केंद्र के समान 60% महंगाई भत्ता देने की मांग

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने और देय तिथि से एरियर का भुगतान करने की मांग की है। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

कर्मचारी संघ ने ज्ञापन में कहा है कि भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा केंद्रीय शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 01 जुलाई 2025 से वृद्धि कर इसे 58 प्रतिशत किया गया था। इसके पश्चात 01 जनवरी 2026 से पुन: 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने 01 जनवरी 2026 से राज्य के शासकीय सेवकों के लिए 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय

कर्मचारियों एवं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।

संघ का कहना है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों की क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। वर्तमान में दैनिक उपयोग की वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन सहित अन्य आवश्यक व्ययों में वृद्धि के कारण कर्मचारियों एवं पेंशनरों पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र एवं राज्य के महंगाई भत्ते की दर में अंतर से राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य की प्रशासनिक एवं विकासात्मक व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, इसलिए महंगाई भत्ते की दर में समानता स्थापित किया जाना कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में होगा। संघ ने मुख्य सचिव से मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए वर्तमान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाए और बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 01 जनवरी 2026 से देय तिथि के आधार पर एरियर सहित प्रदान किया जाए।

अब जमीनी स्तर पर काम करेगी कांग्रेस: दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण अभियान के तहत अलग-अलग संभागों में ब्लॉक अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी बनाने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग से की गई थी। इसके बाद दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतिम चरण में रायपुर संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों के लिए तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसका आज समापन हुआ। रायपुर संभाग के प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ब्लॉक अध्यक्षों को संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी की रणनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, पूरे प्रदेश को 5 संभागों में बांटकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। 3-3 दिन का हमने सभी संभागों का प्रशिक्षण किया। 307 ब्लॉक अध्यक्ष अब भाजपा के

खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आम जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियां बताएंगे। अब जमीनी स्तर पर कांग्रेस काम करेगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, धनेंद्र साहू भी मौजूद रहे।

भूपेश बघेल के काफिले पर हमला पर दीपक बैज ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गौरव गोगई के ऊपर असम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। ये चिंताजनक बात है। पथराव से कई गाड़ियों के कांच टूटे हैं। असम में लोकसभा के उप चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी जनता के रुझान के अनुसार डरी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता हमारे लोगों पर हमला कर रही है। क्या यही लोकतंत्र है? भाजपाइयों में कानून का डर नहीं है। इस घटना की कांग्रेस निंदा करती है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

बलौदाबाजार-भाटापारा ब्लॉक में बंद गोदाम में 20 गायों की मौत मामले में दीपक बैज ने कहा, पूरे प्रदेश में गायें भूख से मर रही हैं। हाइवे रोड में एक्सीडेंट से गाय मर रही हैं। बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग जैसे कई शहरों में 240 से ज्यादा गाय की मौत हुई है। ये सरकार गाय पर राजनीति करती है और गाय को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। गायों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। सरकार कुछ नहीं कर रही है।

स्वतंत्रता दिवस पर वायरल वीडियो के मामले में अजय चंद्राकार के कोर्ट जाने पर दीपक बैज ने कहा, मीडिया में बने रहने के लिए अजय चंद्राकर कोर्ट की शरण ले रहे हैं। वे अपनी टीआरपी बढ़ाने कोर्ट जा रहे हैं। उन्हें कोर्ट जाने दो कोई दिक्कत नहीं है।

रायपुर में बीजेपी पार्षद प्रीतम ठाकुर पर हमला होने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ये पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार में आम जनता असुरक्षित है। बीजेपी नेता भी सुरक्षित नहीं है। पवन साय की गाड़ी में हमला हुआ था। कई बीजेपी नेताओं पर हमला हो चुका है। हमारे पूर्व मेयर को 50 करोड़ की फिरौती को लेकर धमकी मिली है।गणेश पंडाल में चाकूबाजी हो रही है। गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है। कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है।

संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नागरिक आपूर्ति निगम की बैठक संपन्न

रायपुर। नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक आम सभा की बैठक मुख्यालय, नवा रायपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम लेखों को संचालक मंडल की पूर्व आयोजित बैठक में अनुमोदन किए जाने के उपरांत वार्षिक आम सभा की बैठक में अंतिम लेखो पर महालेखाकार नई दिल्ली की टिप्पणीयों पर निगम प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अनुमोदन उपरांत अंगीकार किया गया। बैठक में निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम लेखों पर महालेखकार, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, इसे शीघ्र ही आगामी बैठक में संचालक मंडल से अनुमोदन करा कर सामान्य सभा में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में निगम अध्यक्ष को अवगत कराया गया।

वार्षिक सामान्य सभा की बैठक में निगम प्रबंध संचालक, भोसकर विलास संदिपान, श्री गजपाल सिंह सिकरवार, संयुक्त सचिव, (खाद्य) श्री सीताराम तिवारी, उप सचिव (वित्त), श्री मनोज कुमार मिश्रा, उप सचिव, (कृषि) एवं निगम के अंशधारीगण- श्री अमितोष जान, अवर सचिव, खाद्य श्री संतोष ब्रम्हानंद खापर्डे, एजीएम (वित्त), महेन्द साहू, एजीएम (आईटी), श्री मनोज वर्मा, डिप्टी एजीएम (वित्त) एवं श्री राजेश कुमार सिसोदिया, कार्यापालन संचालक (वित्त), श्री दिनेश कुमार नाग, महाप्रबंधक (प्रशासन) विशेष रूप से उपस्थित थे।

मंत्री राजवाड़े पहुंचीं ग्राम कुंजनगर, महिलाओं से किया संवाद

महतारी वंदन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राहियों से जानी योजनाओं की उपयोगिता

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहीं महिलाओं से सीधे संवाद की पहल को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ग्राम कुंजनगर पहुंचीं। उन्होंने महिलाओं और अन्य हितग्राहियों से आत्मीय संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभ, उनके अनुभवों और परिवार के जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विशेष रूप से महतारी वंदन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही महिलाओं से बातचीत की।

उन्होंने जाना कि योजनाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता महिलाओं की दैनिक आवश्यकताओं, परिवार के खर्च और मातृत्व से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में किस प्रकार सहयोगी बन रही है। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शासकीय योजनाओं से उन्हें आर्थिक संबल और आत्मविश्वास मिला है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ मातृत्व और परिवार के बेहतर पोषण में भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से इन योजनाओं के वास्तविक लाभ और हितग्राहियों के अनुभवों को सामने लाने के साथ शासन और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत किया जा रहा है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ग्रामीण महिलाओं की बातों को गंभीरता से सुना और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े उनके अनुभव जाने। ग्राम कुंजनगर में महिलाओं से हुआ यह संवाद महिला सशक्तिकरण, जनभागीदारी और सेवा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. वि./यां. संभाग नवा रायपुर छ.ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक. 2331/NIT-30/2026-27/व.ले.लि. नवा रायपुर, दिनांक 18/09/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से निम्नालिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का का नाम No of Call	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
30 T0102	Electrification work in 02 Nos Court room at First floor of existing building of District Court Balodabazar District Balodabazar CG **प्रथम आमंत्रण**	4.36

नोट - निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 01/10/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक है। निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

शर्तें :-1) उपरोक्त कार्यों के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियामानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. वि/यां. संभाग
नवा रायपुर (छ.ग.)

जी-262703408/4

अंसारी ने हिंदू राष्ट्रवाद को खतरा बताकर खड़ा किया विवाद

नीरज कुमार दुबे

अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हालिया बयान ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और कांग्रेस की वैचारिक दिशा को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है। नई दिल्ली में एजी नूरानी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में अंसारी ने नूरानी की 2019 में प्रकाशित पुस्तक The RSS: A Menace to India का हवाला देते हुए जवाहरलाल नेहरू की एक कथित टिप्पणी दोहराई थी। अंसारी के अनुसार, नेहरू ने कहा था कि भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं, बल्कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने नागरिक राष्ट्रवाद की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उभार पर भी सवाल उठाए थे। यहां सियासी सवाल खड़ा होता है कि क्या आज के भारत को देखने का नजरिया अब भी दशकों पुराने वैचारिक चश्मे से तय किया जाएगा? सवाल उठता है कि क्या हिंदू दक्षिणपंथ को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताना ही देश की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की पर्याप्त व्याख्या है? उधर, बीजेपी ने अंसारी के बयान को हाथोंहाथ लिया और कांग्रेस की वैचारिक दिशा पर ही सवाल दाग दिया। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि अंसारी ने अनजाने में कांग्रेस की वर्तमान राजनीति को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने कभी कम्युनिज्म को चुनौती माना था, वह आज अल्ट्रा-लेफ्ट की ओर चली गई है। डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने अंसारी द्वारा नेहरू के हवाले को राहुल गांधी की वर्तमान राजनीतिक भाषा से जोड़ते हुए पूछा कि क्या आज की कांग्रेस की वैचारिक जड़ें उसी सोच में हैं? उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस तक कह डाला। लेकिन अंसारी के बयान का दूसरा और अधिक गंभीर राजनीतिक पहलू भी है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे रुझान उभरे हैं जो नागरिक राष्ट्रवाद की स्थापित अवधारणा को चुनौती देकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं। उनके मुताबिक इसमें चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में प्रस्तुत करने और राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह महज इतिहास का संदर्भ नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा वैचारिक आरोप है। इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर और तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति से पद की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा होती है। योगी ने अंसारी के बयान को भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति के प्रति अपमानजनक बताया तथा आरोप लगाया कि इससे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बयान में हिंदू परंपरा को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। उधर, भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी अंसारी से माफी की मांग की और दावा किया कि उनकी टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय के भी अनेक लोग असहज हुए हैं। साथ ही भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विभाजन के बाद भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और विभिन्न धार्मिक समुदायों के साथ रहने की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश सफल नहीं होगी। यही नहीं, कई अन्य मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा भी अंसारी की टिप्पणियों से दूरी बनाने और सामाजिक सौहार्द पर जोर देने की खबरें सामने आई हैं। बहरहाल, अब असली राजनीतिक बहस यही है कि क्या भारत को समझने के लिए हिंदू बनाम कम्युनिज्म की पुरानी वैचारिक तुलना पर्याप्त है? क्या हिंदू राष्ट्रवाद को स्वत: खतरा मानना उचित है?

छात्रों की गूंज और डीयू चुनाव

अजय बोकिल

यह सिर्फ संयोग नहीं था कि जहां एक तरफ इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में युवा अपनी समस्याएं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने रख रहे थे, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के छात्र संघ पदाधिकारी चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। इन दो समानांतर घटी घटनाओं ने कुछ सवालों को फिर से रेखांकित किया है। पहला तो यह कि राहुल गांधी जिस तरह युवाओं के बीच अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वह वोटों में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रही है और होगी तो कैसे? दूसरे, युवाओं को अपनी समस्याएं राहुल गांधी को बताना क्यों ज्यादा सहज और परिणामूलक लग रहा है, बजाय उन राज्य सरकारों के जहां ये 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम हो रहे हैं? तीसरा, राहुल गांधी गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसे कार्यक्रम कर लोकप्रियता पाने के अलावा छात्रों की कोई ठोस मदद कैसे कर पाएंगे?

चौथा, राहुल कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे कार्यक्रम क्यों करते, जहां वह अपनी सरकारों के जरिए सचमुच छात्रों की समस्या हल करवा सकते हैं? पांचवां, राहुल के इन कार्यक्रमों से भाजपा सरकारों को क्या सीखना चाहिए, क्या वो खुद ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों की जायज मांगों को हल करने की पहल नहीं कर सकतीं? छठा, किसी गंभीर कार्यक्रम में कमेडियनों की एंट्री से क्या संदेश जाता है, जैसा कि राहुल के कार्यक्रम में हुआ? सातवां, युवाओं में लोकप्रिय होना एक बात है और इस लोकप्रियता को राजनीतिक लाभ में कन्वर्ट करने का हुनर अलग बात है। क्योंकि सिर्फ एक पहिए से सियासत की गाड़ी नहीं चलती। राजनीति में संवाद के साथ-साथ कुशल प्रबंधन भी उतना ही अहम है, अन्यथा ऐसी लोकप्रियता अस्थायी और मुद्दा सापेक्ष बन कर रह जाती है। यानी कि 'छात्रों की गूंज' में झलकी युवाओं की बेचैनी क्या सत्ता परिवर्तन की चाहत का भी कोई गंभीर संकेत है या नहीं?

ये तमाम सवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के युवाओं से जुड़ने की 'छात्रों की गूंज' श्रृंखला के तहत इंदौर में 19 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम के बाद उठे हैं। यूं तो यह एक रूटीन आयोजन ही था, लेकिन भाजपा ने जिस तरह इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष अड़ंगे लगाए, उससे इसे ज्यादा हाइप मिल गया। नतीजतन बहुत बड़ी संख्या में छात्र इस कार्यक्रम में पहुंचे। आयोजकों का दावा है कि इस कार्यक्रम के लिए सात लाख छात्र-छात्राओं ने ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराया। जबकि भाजपा का कहना है कि कार्यक्रम में छात्र कम कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा थे। जो भी हो, लेकिन जो थे, वो युवा थे, यह तो वीडियो में साफ झलक रहा था।

इस कार्यक्रम में मंच पर बुलाए गए अधिकांश युवाओं की यही शिकायत दिखी कि राज्य में शिक्षा की सुविधाएं ठीक नहीं हैं, समय पर परीक्षाएं नहीं होतीं, होती हैं तो रिजल्ट टाइम पर नहीं आता, नर्सिंग के लाखों छात्रों की स्थिति और बदतर है, न उनके पास डिग्री है और न ही जल्द मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रदेश के तमाम असली-नकली नर्सिंग कॉलेज कानूनी पेंच में फंसे हैं। सरकारी भर्तियां बहुत कम हैं, पहले तो विज्ञापन ही नहीं निकलता, निकलता है तो दस गल्तियां होती हैं, ओबीसी सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण चाहते हैं, वो भी नहीं मिल रहा।

प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नहीं होतीं, होती हैं तो बरसों रिजल्ट जारी नहीं होता। हो भी गया तो नियुक्ति पत्र पाने के लिए चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। मंच पर जो कहा गया उसमें जेनुइन बात यही है कि चूंकि छात्रों की बहुत-सी जायज समस्याएं हैं, जिन्हें सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उनके निदान करने का सरकार के स्तर पर कोई स्पष्ट और अलग से मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए वो राहुल गांधी के मंच पर जाकर अपनी बात कह रहे हैं। ऐसा कोई मंच है भी तो वह समस्याएं सुलझाने की जगह ज्ञान बांटने से ज्यादा प्रेरित है।

यहां सवाल यह भी है कि राहुल गांधी गैर कांग्रेस शासित राज्यों में 'छात्रों की गूंज' सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? या वो युवाओं के बड़े वोट बैंक के मद्देनजर इसे केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने और यह संदेश देने में मशगूल हैं कि छात्रों को लगे कि कोई तो उनकी बात सुन रहा है। यूं भी छात्रों की गूंज का असल मकसद तो राजनीतिक ही है कि युवा सत्ता परिवर्तन का इंजन बनें। लिहाजा राहुल यह कहकर भाजपा सरकारों को एक्स्पोज कर रहे हैं कि उनके द्वारा शासित राज्यों में युवाओं की कोई सुनवाई नहीं है। वैसे यह तरीका भाजपा नेता भी कांग्रेस शासित राज्यों में अपना सकते हैं, क्योंकि कमोबेश छात्रों की समस्याएं सभी जगह एक-सी हैं। लेकिन वो राहुल गांधी की आलोचना में ही इति श्री मान रहे हैं। कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं दिखती।

इंदौर के कार्यक्रम के साथ भी यही हुआ। इसी आयोजन में अचानक मंच पर एक स्टैंड-अप कमेडियन पुलकित मणि की एंट्री हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नकल करने की कोशिश की। यही नहीं मोदी की माताजी को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जो अभद्रता की श्रेणी में आती है। इसी को लेकर भाजपा ने राहुल पर हमला किया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि अगर मोदी की माताजी पर हमला गलत है तो राहुल की मां पर हमला सही कैसे है? जाहिर है मां किसी की भी हो, कोई भी असभ्य टिप्पणी अक्षम्य है। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद पुलकित मणि का नोएडा में आयोजित स्टैंड अप कॉमेडी शो रद्द कर दिया गया। बता दें कि पुलकित एक विवादित स्टैंड-अप कमेडियन हैं। मेटा उनके दो रील हटा भी चुका है। पुलकित यूपी के ही हैं और फ्रेंच भाषा टीचर तथा अनुवादक हैं। इंस्टाग्राम पर उनका @funnywhoisfunny नाम से हैंडल है। उनके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर बताए जाते हैं। पुलकित को मंच पर बाकायदा बुलाया गया था या वो खुद मंच पर चढ़ गए, यह साफ नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों ने मंच की गंभीरता को कम ही किया। खुद राहुल गांधी को उन्हें रोकना चाहिए था बजाए उनसे गले मिलने के।

बहरहाल पुलकित को अलग रखें तो इस बार 'छात्रों की गूंज' में राहुल गांधी ने 'सिस्टम' पर तगड़ा हमला करते हुए छात्रों को यह बताने की कोशिश की कि यह 'सिस्टम' ही आप को आगे बढ़ने से रोक रहा है। 'सिस्टम' बोले तो उन्होंने प्रधानमंत्री सहित देश को चलाने वाले छह धुरंधरों के नाम लिए। लेकिन राहुल भूल गए कि सरकार किसी की भी हो, 'सिस्टम' चलाने वाले चंद लोग ही होते हैं। उसकी मानसिकता एक सी रहती है। जब उनकी सरकार थी, तब भी सिस्टम में ऐसे ही लोग थे। बस, सरकार के साथ चेहरे बदल जाते हैं। वो 'सिस्टम' भी फेल था, इसीलिए कांग्रेस की सत्ता गई।

और सरकार ही क्यों, उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस चलाने वालों का 'सिस्टम' भी पार्टी को मजबूत होने से कैसे रोक रहा है, यह भी देखा जाना चाहिए। वरना छात्रों और युवाओं के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का असर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव नतीजों पर भी दिखता। हालांकि यह तर्क भी दिया जा सकता है कि डीयू के नतीजों को समूचे देश के आईने में नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी डीयू में भाजपा के छात्र संगठन अभाविप की पकड़ पहले से मजबूत रही है, इसलिए वहां छात्र संघ के चार में से तीन पदों पर अभाविप का कब्जा कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी। एक पद निर्दलीय के खाते में गया।

दो माह पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों में बदलाव के चाहत की गूंज डीयू के चुनावों में भी सुनाई देगी, यह उम्मीद बहुतों को थी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, बल्कि कांग्रेस की अंतर्कलह, भाई-भतीजावाद और गलत टिकट वितरण की वजह से एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। इसके पीछे भी वही 'सिस्टम' है जो कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब प्रश्न यह है कि जब आप अपने 'भीतरी सिस्टम' को सुधार नहीं पा रहे हैं तो 'दूसरे के सिस्टम' को गरियाने भर से क्या होगा? बेहतर होगा कि राहुल कांग्रेस शासित राज्यों में छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं कैसे हल की जाती हैं, इसका कोई रोल मॉडल भाजपा शासित राज्यों के सामने रखते तो वह ज्यादा व्यावहारिक और सार्थक होता।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

6- बौद्धों के दार्शनिक सम्प्रदायों का विभाग

गतांक से आगे...

सारे बौद्ध सम्प्रदायों को एक जगह दिखाने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि उनके पृथक् पृथक् साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को सामान्यरूपेण बौद्ध दर्शन के अन्तर्गत समझ लिया जाता है। जिससे उन सिद्धान्तों के विषय में बहुत अधिक परस्पर गड़बड़ हो जाती है। इसका स्पष्ट उदाहरण माधवाचार्य कृत सर्वदर्शनसंग्रह में मिलता है। बौद्ध दर्शन के अन्तर्गत इस ग्रन्थ में जो कुछ भी लिखा गया है, उसमें कई अनेक दृष्टियों से दोष और भूम के साथ साथ यह भी एक बड़ी त्रुटि है, कि सम्प्रदाय विशेष के सिद्धान्त बौद्धों के सामान्य सिद्धान्तों के रूप में दे दिये हैं। बस्तुत: यह आवश्यक है कि बौद्धों के दार्शनिक सम्प्रदायों को वैदिक दार्शनिक सम्प्रदायों के समान ही एक दूसरे से पृथक् पृथक् रक्खा जावे। बौद्धों के मुख्य मुख्य दार्शनिक सम्प्रदाय कौन कौन से हैं, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

सर्वदर्शनसंग्रह में जो कि 14वीं शताब्दी का ग्रन्थ है, जब कि बौद्ध दर्शनों के स्वरूप को भारत के वैदिक-दर्शन-सम्प्रदाय के लोग भूल चुके थे, बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदायों का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय और उससे पहले वैदिक क्षेत्र के दार्शनिक इन चार सम्प्रदायों को ही समझते थे। 14वीं शताब्दी से कुछ पहले से लेकर वाद के सभी दार्शनिक ग्रन्थों में इन चार बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों का वर्णन है। परन्तु बौद्धों के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में बौद्ध दर्शन को इन चार सम्प्रदायों में बांटा गया हो, ऐसा नहीं मिलता। आश्चर्य की बात तो यह है कि आधुनिक समय के पाश्चात्य लेखक या पाश्चात्यशैली के भारतीय लेखक, जिन्होंने भारतीय दर्शन के इतिहास आदि लिखे हैं, सर्वदर्शनसंग्रह के अनुसार इन्हीं चार बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों का वर्णन करते हैं, मानों कि बौद्ध दर्शन का इन चार सम्प्रदायों में विभाजन सर्वथा प्रामाणिक बात हो। **क्रमश: ...**

जनकवि के साथ राष्ट्रकवि भी थे रामधारी सिंह दिनकर

अमृता गोस्वामी

कवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगुसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। मात्र तीन साल की छोटी सी उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया था जिसके कारण उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1928 में दिनकर पटना आ गए, यहां इतिहास में ऑनर्स के साथ 1932 में उन्होंने बीए किया और एक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए।

हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी राष्ट्र प्रेम और ओजस्वी कविताओं के लिए एक जनकवि के साथ-साथ राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी मिलने के बाद तक उनकी लिखी कविताएं, उनके लिखे लेख, निबंध, लोगों में आजादी के प्रति, संस्कृति के प्रति जोश जगाने वाले रहे।

कवि दिनकर की प्रारंभिक रचनाएं उनके काव्य संग्रह 'प्राणभंग' और 'विजय संदेश' थे जो उन्होंने 1928 में लिखे थे। इसके बाद दिनकर ने कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखीं जिनमें रेणुका, 'परशुराम की प्रतीक्षा', 'हुंकार' और 'उर्वशी' काफी प्रचलित रचनाएं हैं। दिनकर के लिखे निबंधों में अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, वटपीपल, आधुनिक बोध इत्यादि प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। उनकी लिखी पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' काफी चर्चित रही जिसे 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।

हिन्दी के अलावा कवि दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। 1947 में वे प्रचार विभाग के उपनिदेशक और फिर मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिन्दी विभागाध्यक्ष बने। वर्ष 1952 में दिनकर को राज्यसभा के सदस्य के लिए चुना गया और 12 वर्षों तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार भी बने।

कविता रचने का भाव रामधारी सिंह दिनकर के मन में उनके घर में प्रतिदिन होने वाले रामचरित मानस के पाठ को सुनकर जागा। पहले जहां छायावादी कविताओं का बोलबाला था दिनकर ने हिंदी कविताओं को छायावाद से मुक्ति दिलाकर आम जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। दिनकर ने अधिकतर कविताएं वीर रस में लिखीं। जनवादी, राष्ट्रवादी कविताओं के अलावा दिनकर ने बच्चों के लिए भी बहुत ही सुंदर कविताओं की रचना की।

बच्चों के लिए लिखी उनकी कविताओं में 'चांद का कुर्ता', 'सूरज की शादी', 'चूहे की दिल्ली यात्रा' इत्यादि प्रमुख हैं। दिनकर की सशक्त लेखनी के लिए उन्हें कई नामी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मविभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ इत्यादि से सम्मानित किया गया। 1968 में उन्हें राजस्थान विद्यापीठ ने साहित्य-चूड़ामणि से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें वर्ष 1972 में उनकी काव्य रचना 'उर्वशी' के लिये प्रदान किया गया। हरिवंश राय बच्चन ने उनके लिए कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं चार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने चाहिए थे, जो उनकी गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी के सेवा के लिए अलग-अलग दिए जाते। 24 अप्रैल, 1974 को कवि दिनकर का निधन हो गया।

राशन इकट्ठा कर लो...यूरोप में क्या बड़ा होने वाला है!

अभिनय आकाश

क्या यूरोप एक बहुत बड़े महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है? क्या तीसरे विश्वयुद्ध की आहट अब इतनी करीब आ चुकी है कि सरकारों ने अपने नागरिकों से सीधे तौर पर राशन और पानी जमा करने को कह दिया है? ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि इस वक्त पूरे यूरोप की जमीनी हकीकत बन चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों खुले तौर पर कह रहे हैं कि यह वक्त बेहद मुश्किल है और सबको एक साथ खड़ा होना होगा। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक, यूरोप के तमाम मुल्कों में जनता को बाकायदा हिदायत दी जा रही है कि घरों में राशन, सूखा खाना, पीने का पानी और ईंधन स्टॉक करना शुरू कर दें। यूरोप का शायद ही कोई ऐसा अखबार बचा हो जिसकी हेडलाइन में यह खौफ साफ न छलक रहा हो। दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो अमेरिका लगभग ग्रीनलैंड की सुरक्षा का पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले चुका है और साफ कह दिया है कि अब इस पूरे इलाके की रक्षा अमेरिकी बूट्स करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रूस की तरफ से यूरोप की खुफिया एजेंसियों को ऐसे कौन से इनपुट्स मिले हैं, जिसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया है? क्यों यूरोपीय राजधानियों में बंकरों की धूल झाड़ी जा रही है और सेनाओं को स्टैंडबाय पर रहने का फरमान जारी हो चुका है? क्या मॉस्को से कोई ऐसा बड़ा तूफान उठने वाला है जो पूरे यूरोप को अपनी जद में ले लेगा? आज इसी का एमआरआई स्कैन करते हैं।

यूक्रेन ने 20 सितंबर को यहां कई ड्रोन हमले किए हैं। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से आने वाले 1600 ड्रोंस को उसने इंटरसेप्ट किया है और वीडियो से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हमले में दो लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी और सेना के लॉजिस्टिक ठिकाने को टारगेट किया। कई इमारतों को इसमें नुकसान भी

पहुंचा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब रूस में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। वोटिंग का अंतिम दिन था। लोअर हाउस जो संसद है रूस का उसके लोअर हाउस के लिए यह वोटिंग थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वडदमीर जेलस्की ने खुद हमले की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, हमने रूस की ऑयल रिफाइनरी और सेना के लॉजिस्टिक ठिकाने को टारगेट किया। यह वही अरबों डॉलर का तंत्र है जहां रूस अपने डिफेंस का सामान तैयार करता है। जेलस्की ने यह भी बताया हमले में यूक्रेन ने क्या-क्या इस्तेमाल किया है।

यूक्रेन ने हमले के लिए ठीक ऐसा वक्त चुना जब व्लादमीर पुतिन के 26 साल के एक छत्रराज को नई ताकत देने के लिए वोट डाले जा रहे थे। ठीक उसी वक्त जेलस्की के ड्रोन ब्रिगेड ने ऑपरेशन मॉस्को को अंजाम दे दिया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन हमलों में तीन लोगों की जान चली गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मतलब साफ है कि यह सिर्फ आसमान में उड़ते हुए यूक्रेन के ड्रोंस नहीं थे बल्कि रूस के दिल माने जाने वाले क्रिमिया पर यूक्रेन का लॉन्ग रेंज अटैक था। मॉस्को के आसमान में जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए उससे रूस की एयर डिफेंस क्षमता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि यूक्रेन के हमलों का निशाना बना है मॉस्को का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो धमाकों के बाद पूरी तरह से स्वाहा हो गया है। यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। क्योंकि तेल और गैस से होने वाली कमाई रूस की युद्ध मशीन के लिए बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में रूसी तेल रिफाइनिंग क्षमता पर यूक्रेनी हमलों से रूसी ईंधन की सप्लाई और कीमतों पर भी असर पड़ना तय है। उधर मॉस्को में 21 मंजिला एक रिहाइशी इमारत में ड्रोन टकराने से भीषण आग लग गई। इस बीच यूक्रेन के इस सबसे बड़े ड्रोन अटैक पर बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि आखिर चुनाव के अंतिम दिन मॉस्को पर इतना बड़ा हमला क्यों किया गया? इसके जवाब में मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने बताया कि यूक्रेन के हमले का सीधा मकसद रूसी संसदीय चुनाव में खलल डालना था।

रूसी भाषा में बोलते व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सामने आया है। जिसमें वो कह रहे हैं कि नाटो हमारी तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। नए-नए इलाके में घुसने कोशिश कर रहा है। अब हमने फैसला किया है कि उनके खिलाफ अब निर्णायक जंग छेड़ दिया जाए। अब हुआ यह कि जैसे ही एक तो रूस के राष्ट्रपति ने कह दिया कि मारेंगे जरूर चाहे जो हो जाए और ऊपर से वहां राशन पानी इकट्ठा करने की बात हो ही गई। सारे यूरोप वाले कह रहे हैं कि हमारी रक्षा तो अमेरिका करता था। तो अमेरिका बचाएगा कि नहीं हमें? डोनाल्ड ट्रंप अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया कि हम यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात है वापस ले रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि गल्फ नेशन में जो अमेरिकन सैनिक हैं हम ईरान के हाथों मरने नहीं दे सकते। उसको भी वापस ले लेंगे।

यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से आई एक ताजा और बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरे पश्चिमी खेमे में खलबली मचा दी है। खुफिया अधिकारियों का दावा है कि रूस बहुत जल्द नाटो की ताकत और उसकी एकजुटता की परीक्षा ले सकता है, और यह संभावित हमला सालों में नहीं, बल्कि कुछ ही महीनों के भीतर देखने को मिल सकता है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपनी संसद में साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि मॉस्को आने वाले महीनों में ड्रोन या मिसाइलों के जरिए नाटो की जमीन को निशाना बना सकता है। टस्क के मुताबिक, पुतिन का सीधा मकसद यह साबित करना है कि नाटो का सबसे ताकतवर सुरक्षा कवच यानी आर्टिकल 5, जमीन पर सिर्फ एक किताबी थ्योरी है, हकीकत नहीं। इस चेतावनी की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने टस्क के इन दावों को बेहद सटीक और पुख्ता सबूतों पर आधारित बताया है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि मैक्रों ने पेरिस में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और राष्ट्रपति पद के दावेदारों की एक आपातकालीन बैठक तलब कर ली, जहां रूस के इस बढ़ते खतरे पर बंद कमरों में रणनीति तैयार की जा रही है। यह चिंता तब बढ़ रही है जब इस हफ्ते के आखिर में न्यूयॉर्क में ह जनरल असेंबली की बैठक होने वाली है और साथ ही रूस-यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ़ से हवाई हमले तेज़ हो गए हैं। रविवार तड़के कीव ने मॉस्को और रूस के दूसरे इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं। यह इस युद्ध के दौरान किए गए सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था। द गार्जियन को दिए गए अलग-अलग साक्षात्कारों में पश्चिमी खुफिया प्रमुखों ने पुतिन के अगले खतरनाक कदम का जो खाका खींचा है, उसने नाटो मुख्यालय से लेकर तमाम यूरोपीय देशों की नींद उड़ा दी है। चेक गणराज्य की सुरक्षा सेवा %बीआईएस% के प्रमुख माइकल कोउडेल्का ने प्राग स्थित अपने मुख्यालय में एक दुर्लभ इंटरव्यू के दौरान बेहद सनसनीखेज अंदेशा जताया है। कोउडेल्का के मुताबिक, केवल ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक ही नहीं, बल्कि रूस से सटी नाटो सीमा पर रूसी सेना की एक सीमित जमीनी घुसपैठ यानी %स्मॉल-स्केल इनवेजन% भी क्रेमलिन के प्लान का सीधा हिस्सा हो सकता है। माइकल कोउडेल्का ने चेताते हुए साफ कहा यह पूरी तरह मुमकिन है। रूस की योजना में एक सीमित सैन्य घुसपैठ, फॉल्स-फ्लैग उकसावे वाली साजिशें और नाटो देशों के भीतर एक बड़े पैमाने का इनफ्लुएंस कैंपेन शामिल हो सकता है।

आज का इतिहास

1739 रूस और तुर्की ने बेलग्राद शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
1803 असाए की लड़ाई में ब्रिटिश-भारतीय सेनाओं ने मराठा सेना को हराया।
1857 रूस का जंगी जहाज लेफोर्ट फिनलैंड की खाड़ी में तूफान में घिर कर लापता, 826 लोगों की मौत।
1863 राव तुला राम का निधन।
1879 रिचर्ड रोड्स ने सुनने में मदद करने वाली शुरूआती मशीन बनाई, इसे आडियोफोन नाम दिया गया।
1929 बाल विवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी गई। यह शारदा कानून के नाम से जाना गया।
1955 पाकिस्तान ने बगदाद की संधि पर दस्तख्त किए।
1958 ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया था।
1965 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में युद्धविराम का ऐलान।
1970 अब्दुल रजाक बिन हुसैन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने थे।
1976 सोयूज-22 पृथ्वी पर वापस लौटा।
1992 यूगोस्लाविया का संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासन हुआ था।
1995 इस्रायल एवं फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मध्य पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी स्वशासन के संबंध में समझौता।
2000 सिडनी ओलम्पिक में संयुक्त राज्य अमेरिका की धाविका मैरियन जोन्स ने 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता था।
2001 ब्रिटिश व तालिबान सेना के बीच गोलाबारी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत व पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटाये गए थे।
2002 जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रीएडर पुन: सत्ता में आये थे।
2003 भूटान में लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार किया था।
2004 हैती में तूफान से आई बाढ़ में कम से कम 1,070 लोग मारे गए थे।
2006 पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने भारतीय प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह को वार्ता का निमंत्रण दिया था।
2009 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय उपग्रह ओशन सैट-2 समेत सात उपग्रह कक्षा में स्थापित किए।
2011 फ्रांसीसी न्यायालय ने हिंद अहमास और नजाइत अली नाम की दो मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने के लिए पहली बार सजा के रूप में 120 और 80 यूरो जुर्माना लगाया था।
2020 भारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें पांच भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान था।

जेन जी : भारतीय जनता पार्टी को धार अभी पैनी करनी होगी

अकु श्रीवास्तव

पहले पंजाब विश्वविद्यालय और शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के चुनाव नतीजे आने के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आला नेताओं की धुकधुकी थम गई होगी लेकिन उनके लिए कॉकरोच जनता पार्टी के ध्वज तले निकली जेन जी को संभाले रखने में अब भी काफी और लगातार मशक्कत करनी होगी। इस चुनाव ने फिर यह तय किया कि चुनावों का नेरेटिव (आख्यान) कुछ बड़ी घटनाओं पर ही ज्यादा आश्रित होता है। दिल्ली में छात्रों के इलाके में एक भवन का गिरना इतना बड़ा मुद्दा बना देगा, यह राजनीतिक दलों को भी तत्काल समझ में नहीं आया। डूसू के चुनाव सिर पर होने के कारण राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाने शुरू किए और रेखा गुप्ता की सरकार को 10 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा करनी पड़ी और शायद डिलीवरी के अच्छे रिकॉर्ड की वजह से छात्रों ने इस वायदे पर भरोसा भी कर लिया।

यूं तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद हर छोटा-बड़ा नेता हैलो-हाय में जुट गया है और उनके मुद्दों को लेकर तमाम रणनीतियां बन रही हैं। नौकरियों की ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं और साथ ही उनको कुछ सरकारें जमीन पर लागू भी करने में सफल दिख रही हैं। पेपरलीक से जन्मे इस उबाल में अब यह सिलसिला फिलहाल तो नहीं दिख रहा है और इसके लिए न्यायपालिका के साथ ही केंद्र और राज्य की सरकारें भी फूंक-फूंक कर छाछ पी रही हैं। लेकिन डूसू के नतीजों में 4 में से 3 सीटों पर कब्जा करने के बाद और कांग्रेस के छात्र संगठन का सफाया करने के साथ भाजपा या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ए.बी.वी.पी.) के पक्ष में यह पक्का माना जा सकता है कि जेन जी पर उसकी पकड़ पक्की हो गई है।

यह सही है कि कॉकरोच आंदोलन के बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई थी और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संभालने की एकतरफा कोशिश शुरू कर दी। रात 1 बजे युवाओं से वीडियो संवाद हुआ। उन कई आयोजनों में प्रधानमंत्री गए, जहां उन्हें युवाओं से बात करने का मौका मिले। पूरे घर के बर्तन बदल डालूंगा की तर्ज पर काम हुए और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि युवाओं के लिए कुछ तो तत्काल किया जा सकता है। हालात सुधर रहे थे तभी सत्य निकेतन की घटना ने और पोल-पट्टी खोल दी। इसे संभालने की कोशिश की।

दूसरी तरफ विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी की टीम ने सघन और तीखा हमला शुरू किया। 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम का फ्रेमवर्क कुछ ऐसा बनाया गया कि राहुल छात्रों-पीड़ितों से सीधी बात करें। इस बातचीत ने भी रंग दिखाना शुरू किया लेकिन यहां पर भी तथ्यों में कमजोरी के कारण इस कार्यक्रम के सामने 'झूठ की गूंज' आ गई और उसका असर थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन असली गूंज तो चुनावी नतीजे ही बताते हैं। डूसू

चुनावों में ए.बी.वी.पी. की विपरीत परिस्थितियों में बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है, खास तौर से तब जब 2 महीने पहले ही चले आंदोलन ने सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन इस जीत के साथ छात्रों की इस गूंज को ज्यादा आवाज मिली कि कांग्रेस या फिर उसके छात्र संगठन को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।

हालांकि अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद ए.बी.वी.पी. के कब्जे में जरूर आ गए हैं लेकिन यदि पिछले वर्ष के आंकड़ों और जीत के अंतर को देखा जाए तो साफ नजर आएगा कि कैंपस में ए.बी.वी.पी. का दबदबा कम हुआ है। पिछले साल यानी 2025 में ए.बी.वी.पी. के आर्यन मान ने 16,196 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार ए.बी.वी.पी. के यश डबाश चुनाव तो जीत गए लेकिन उन्होंने एन.एस.यू.आई. के विजय शंकर मीणा को केवल 2,053 वोटों से हराया। इसी तरह इस बार ए.बी.वी.पी. के लिए सबसे बड़ा झटका उपाध्यक्ष का पद रहा। विद्यार्थी परिषद को बुरी हार का सामना करना पड़ा, वह भी एक निर्दलीय से। निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने 30,634 वोट हासिल कर ए.बी.वी.पी. के ईशु मौर्य को लगभग 13,724 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी। दीपांशु ने अपना पूरा प्रचार अभियान बड़े रोचक और इनोवेटिव तरीके से चलाया। उन्होंने पूरे प्रचार में चप्पल नहीं पहनी और बार-बार कहा कि हॉस्टल की समस्या को हल कराना उनकी प्राथमिकता है।

संयुक्त सचिव पद पर भी इस बार ए.बी.वी.पी. के लक्ष्य राज सिंह को बेहद कड़ी टक्कर मिली। वह सिर्फ 837 वोटों के बारीक अंतर से ही जीत दर्ज कर पाए। यहां तो उन्हें समाजवादी छात्र सभा के विशेष यादव (15,778 वोट) और एन.एस.यू.आई. के गोपाल चौधरी (15,206 वोट) से त्रिकोणीय मुकाबले में कड़ी चुनौती मिली। यानी यदि विपक्ष के दोनों गुटों के वोट नहीं बंटते, तो संयुक्त सचिव का पद भी ए.बी.वी.पी. के हाथ से निकल सकता था। दरअसल इन सबकी वजह पिछले चुनाव भी हैं। पिछले 9 चुनावों में ए.बी.वी.पी. के पैनल ने 6 बार बहुमत से जीत हासिल की। छह बार ए.बी.वी.पी. को 3-3 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन हॉस्टल की कमी, फीस वृद्धि और इंफ्रास्ट्रचर के मुद्दों को लेकर लाचारी बनी रही।

फिर इधर जेन जी के आंदोलन के बाद पेपरलीक और नौकरी संकट ने इन मुद्दों में और आग लगाई। भले ही कांग्रेस की छात्र इकाई एन.एस.यू.आई. कोई सीट नहीं जीत पाई लेकिन उनके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने ए.बी.वी.पी. को आखिरी राऊंड तक कड़ी टक्कर दी। साथ ही वामपंथी संगठनों और क्षेत्रीय दलों ने भी ए.बी.वी.पी. के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई। इस तरह भले ही ए.बी.वी.पी. के लिए 2026 के डूसू चुनाव परिणाम काफी कुछ बयां करते हैं। संगठन ने संगठनात्मक मजबूती और कोर वोट बैंक के कारण सत्ता तो बचा ली लेकिन जीत का घटता मार्जिन और उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय की बड़ी जीत यह साफ दर्शाती है कि कैंपस की राजनीति में अब ए.बी.वी.पी. का एकछत्र दबदबा उतना मजबूत नहीं रहा। वह भी तब, जब केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भी बहुमत से सरकार। दिल्ली के सभी सांसद उसके हैं।

भाजपा के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें पराजय पूरा नैरेटिव बदल सकती थी। यह उस दिशा में और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब केंद्र में भाजपा की सरकार है लेकिन सही दिशा के कारण भाजपा को यहां मिली सफलता उसकी दिशा को आगे बड़ा सकती है या यह कहना चाहिए कि उसे युवाओं के लिए अपनी धार और पैनी करनी होगी। खास तौर से तब, जब अगले 5-6 महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इनमें से 4 राज्यों में फिलहाल उनकी सरकारें हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए भी कई सबक हैं। कॉकरोच पार्टी की सफलता पर सवार होकर आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते।

सरकारी स्कूलों में सुधार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना

मनु जोसेफ

केरल को छोड़कर, शायद, भारतीय राजनेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की तीसरे दर्जे की हालत से कभी भयभीत नहीं हुए, न ही सरकारी अस्पतालों, ट्रेनों या मतदाताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी चीज की स्थिति से। वे कभी इस बात से भी नहीं डरे कि उनकी रहस्यमय रूप से अर्जित संपत्ति उजागर हो जाएगी। ऐसा लगता है मानो भारत के लोग किसी ऐसी चीज के लिए वोट नहीं करते जो वास्तव में मायने रखती हो। लेकिन अब कुछ नया हो रहा है, जिसका उन्हें शायद एहसास नहीं है कि वह राजनीतिक सुनामी बन सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन पूरे देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति को उजागर करके खुद को जीवित रखे हुए है। यह लंबे समय से केवल राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, बल्कि मीडिया के लिए भी एक गैर-आकर्षक मुद्दा रहा है। लेकिन ऐसे कारण हैं जिनसे सरकारी स्कूलों के लिए लड़ाई बड़ी राजनीति बन सकती है। खासकर अब, जब भारतीय समाज पुराने, बेकार मुद्दों से ऊबता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में एक सरकारी स्कूल हमारे साथ जो कुछ भी गलत है, उसका प्रतीक है। कुछ स्कूलों में इमारतें नहीं हैं, कुछ में शिक्षक नहीं हैं। लाखों बच्चे ऐसे स्कूलों से गुजर चुके हैं, जहां शायद उन्हें कोई शिक्षा ही नहीं मिली। मुख्य रूप से, एक सरकारी स्कूल भ्रष्टाचार, अयोग्यता, कार्य-नैतिकता की कमी और अवमानना को उजागर करता है। सरकार की सभी बुराइयां और विफलताएं एक ही इमारत में समा जाती हैं, जो लोगों की समझ से कहीं अधिक भावनात्मक चीज है। एक सरकारी स्कूल केवल भारत के बहुसंख्यक लोगों के लिए एक परिचित दृश्य ही नहीं, बल्कि ऐसी चीज है जो उनमें से अधिकांश से जुड़ी हुई है। उनके बच्चे वहां पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन वह आमतौर पर इतना खराब होता है कि भारत के नए निम्न-मध्यवर्ग पर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के साहसी प्रयास का बड़ा खर्च डाल देता है। इसलिए अब, जब एक चतुर संगठन ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, सरकारी स्कूल खराब शासन का अप्रत्याशित प्रतीक बन सकता है। 'कॉकरोच' सरकारी स्कूलों में घुस रहे हैं और हमें ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हमें झकझोरती हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वे अपने खिलाफ चल रहे राजनीतिक उपहास के बावजूद ऐसा करना जारी रख पाए हैं। यह उनके उद्देश्य के लिए ठोस समर्थन का संकेत देता है, भले ही यह हमेशा स्पष्ट न हो। एक और कारण कि अनुभवी राजनेता इसका मुकाबला नहीं कर पाए हैं, यह कि सार्वजनिक शिक्षा को बदलने की आवश्यकता के खिलाफ कोई नैतिक तर्क नहीं है। इसमें उस तरह की अस्पष्टता नहीं है जो किसी बेकार सांस्कृतिक मुद्दे में होती है। उच्च शिक्षा के बारे में तर्क हो सकते हैं लेकिन किसी बच्चे को स्कूल से दूर रखने के पक्ष में तर्क करना कठिन है, चाहे वह सरकारी स्कूल ही क्यों न हो। एक स्कूल, अपनी कमियों के बावजूद, एक अत्यंत नैतिक विचार है। यह विचार कि एक बच्चे को मानव जाति द्वारा ज्ञात सभी बुनियादी बातें सीखनी चाहिएं। सीजनल राजनेताओं ने पहले तो इंकार करके कॉकरोचों का सामना किया, फिर उन्होंने वादा किया कि वे स्कूलों को बदल देंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि इसे अच्छी तरह कैसे कहा जाए। उन्हें बेकार मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से पेश करने या खोखले वादे करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अधिकांश को यह पता ही नहीं लगता कि वास्तव में क्या किया जाना चाहिए।

क्या वाकई उत्तरप्रदेश के चार टुकड़े होने वाले हैं?

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी मौसम अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं है, लेकिन सियासी चौपाल पर ऐसा मुद्दा उछल गया है, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में बंटेगा और जातीय जनगणना के बाद इस दिशा में रास्ता साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, राजभर ने पूर्वांचल के अलग राज्य बनने पर उसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने समाज के व्यक्ति का दावा भी ठोक दिया।

देवरिया और अंबेडकरनगर में दिए गए अपने बयानों में ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि जातीय जनगणना के बाद राज्य के पुनर्गठन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राजभर ने जिन चार हिस्सों की बात की, उनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वांचल में राजभर समाज का बड़ा वोट आधार है, इसलिए अलग राज्य बनने पर पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज का बेटा होगा। उल्लेखनीय है कि यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है।

देखा जाये तो राजभर ने सिर्फ राज्य के नक्शे पर लकीर खींचने की बात नहीं की है बल्कि उस लकीर के पार सत्ता की कुर्सी पर भी अपना सामाजिक दावा रख दिया है। यही वजह है कि यह मामला महज प्रशासनिक पुनर्गठन की बहस नहीं रह जाता, बल्कि

उत्तर प्रदेश की जातीय और क्षेत्रीय राजनीति के बीच सीधा उतर जाता है।

वैसे राजभर ने कोई नया कुआं नहीं खोदा है। उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की मांग दो दशक से ज्यादा समय से अलग-अलग रूपों में उठती रही है। सबसे ठोस पहल नवंबर 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार ने की थी। तत्कालीन विधानसभा ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था। मायावती सरकार का तर्क था कि इतने विशाल राज्य में प्रशासन और विकास को प्रभावी ढंग से चलाना कठिन है और छोटे राज्य क्षेत्रीय जरूरतों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं।

प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, लेकिन आगे मामला नहीं बढ़ा। 2014 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2011 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और केंद्र के पास उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था।

यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य या हरित प्रदेश की मांग भी पुरानी है। राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक अजित सिंह समेत कई नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग राज्य की वकालत की थी। गन्ना, खेती, कारोबार, उद्योग और दिल्ली की नजदीकी को इसके पक्ष में प्रमुख तर्कों के तौर पर रखा जाता रहा है। मगर पूर्वांचल की कहानी अलग है। यहां समर्थक कहते रहे हैं कि विशाल आबादी, आर्थिक पिछड़ापन, रोजगार के लिए पलायन और लखनऊ से दूरी के कारण क्षेत्र को अलग प्रशासनिक इकाई मिलनी चाहिए। बुंदेलखंड के लिए भी अलग राज्य की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन उसकी पेचीदगी यह है कि प्रस्तावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है।

देखा जाये तो मोटे तौर पर पुराने प्रस्तावों में पश्चिम प्रदेश में पश्चिमी और कुछ मध्य-पश्चिमी जिलों का बड़ा हिस्सा, अवध प्रदेश में मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे जिले तथा पूर्वांचल में वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका शामिल रहा है। इन सीमाओं को लेकर अलग-अलग प्रस्तावों में फर्क भी रहा है।

छोटे राज्यों के समर्थकों का तर्क है कि छोटा प्रशासन ज्यादा चुस्त होगा, क्षेत्रीय समस्याओं पर सरकार की पकड़ बढ़ेगी और विकास की प्राथमिकताएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तय की जा सकेंगी। विरोध में यह सवाल भी उठता है कि क्या केवल राज्य छोटा कर देने से गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और क्षेत्रीय असमानता खत्म हो जाएगी? नए राज्यों के गठन के साथ राजधानी, विधानसभा, उच्च न्यायालय, सरकारी कर्मचारियों, संपत्तियों, कर्ज, राजस्व और संस्थानों के बंटवारे जैसी बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियां भी सामने आती हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 3 साफ करता है कि नए राज्य का गठन, मौजूदा राज्य की सीमा या क्षेत्र में बदलाव का अधिकार संसद के पास है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। प्रभावित राज्य की विधानसभा से उसके विचार मांगे जाते हैं, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। यानी अगर कभी उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है तो मामला लंबी संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया से होकर गुजरेगा।

बहरहाल, फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में पुरानी चिंगारी पर फिर से फूंक मार दी है। अब देखना यह है कि यह सिर्फ चुनावी मौसम की गरमागरम हुंकार बनकर रह जाती है या सचमुच उत्तर प्रदेश के नक्शे पर नई लकीर खींचने की कवायद शुरू होती है। क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात बड़ी पुरानी है, यहां चुनाव आते ही मुद्दे सिर्फ उठते नहीं, कई बार पूरे भूगोल को ही हिला देने लगते हैं। राजभर के बयान पर प्रतिक्रियाएं आने भी लग गयी हैं। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे चुनावी जुमला बताते हुए कहा है कि केंद्र या प्रदेश सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, जबकि भाजपा नेता संजीव बालियान ने यूपी को चार हिस्सों में बांटने के विचार का समर्थन किया है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से ध्यान भटकाने के प्रयास हो रहे हैं ताकि मूल मुद्दों की ओर जनता का ध्यान नहीं जाये।

अपने ही बुने जाल में फंसा चुनाव आयोग

सनत जैन

दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। मैपिंग और मिसमैच पर 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, सेना के पूर्व उपेंद्र द्विवेदी, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पत्नी, पूर्व जस्टिस रंजना देसाई, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा, सीएजी संजय मूर्ति, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित हजारों व्हीव्हीआईपी के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इन सभी को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का कमाल दिल्ली सहित सारे देश ने देख लिया है। 10 जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तारीख पर तारीख पड़ रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में एसआईआर के लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए, उसके बाद मतदान हुआ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, वहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। पिछले डेढ़ 2 वर्षों से चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और एसआईआर को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला 1 वर्ष से अधिक से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर के लिए बनाए गए नियम जो हर राज्य के लिए अलग-अलग लागू किए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में समय-समय पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैधानिक बता दिया। चुनाव के कुछ महीने पहले जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में एसआईआर करने की प्रक्रिया को ठीक बता दिया। चुनाव आयोग ने जिन लोगों के नाम काटे, उनके नाम उजागर नहीं किये, नोटिस कंप्यूटर के जरिए भेजे जा

रहे हैं। कंप्यूटर मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। उसका सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग ने बनवाया है। कैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, यह भी चुनाव आयोग राजनैतिक दलों को नहीं बताता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मिली संवैधानिक शक्तियों के कारण उसे सर्वशक्तिमान मान लिया है। चुनाव आयोग लगातार मनमर्जी करता चला जा रहा है। इसकी आंच अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचने लगी है। कहा जा रहा है, जब गृह मंत्रालय में जस्टिस सूर्यकांत की पदोन्नति को लेकर जो फाइल आईबी की ओर से गई थी, उस समय गृह मंत्रालय ने आईबी की जांच को प्रधानता नहीं दी। पंजाब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत की पदोन्नति को लेकर एक अहम भूमिका ज्ञानेश कुमार की थी। इस तरह के आरोप अब खुलकर लगने लगे हैं। चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन सब की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ही हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो याचिका लगी थी, वह अभी तक लंबित है। उस पर कोई फैसला नहीं आया है। इतने लंबे समय से एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। अब रही सही कसर कंप्यूटर से जो मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं, उसमें बड़े-बड़े महारथियों के नाम आसानी से काटे जा रहे हैं, या उन्हें नोटिस जारी हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का परिवार, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी एसआईआर के शिकार हो गए हैं। जिसके कारण एसआईआर अब तूल पकड़ गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग को इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। करोड़ों मतदाताओं से उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए हैं। जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें राज्य शासन से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जगह-जगह उन पर अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। बंगाल के एक संपादक महोदय के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण वह अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाए।

सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। उसके बाद भी यह खेल लगातार खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जजों को भी अपील सुनने के काम में लगा दिया। 38 लाख अपीलों में करीब 1 लाख अपीलों की सुनवाई हुई है। इसमें 91 फ़ीसदी मतदाता सही पाए गए हैं। अभी भी 37 लाख लोग ट्रिब्यूनल के चक्कर लगा रहे हैं। इसको निपटने में 20 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। रोज कमाने खाने वाले उन करोड़ों लोगों को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर करके उनके नागरिक अधिकार में डाका डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को सुन रही है, देख रही है, समझ रही है। उसके बाद भी किन कारणों से तारीख पर तारीख देकर मामले को टाल रही है। इसको लेकर अब देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सड़कों पर उतर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में जो एसआईआर हुई है, उसने चुनाव आयोग को अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंसा दिया है। आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस जाल से कैसे बाहर निकल पाएंगे, इसकी चर्चा अब सारे देश में हो रही है। अभी तक मतदाता चुप था। समझ नहीं पा रहा था, कि वह अपनी लड़ाई कैसे लड़े। अब 13 करोड़ से ज्यादा लोग नागरिक अधिकार से वंचित हो गए हैं। यह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि सड़कों पर आ जाएंगे, तो क्या होगा? इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कानून और नियमों का पालन तभी तक होता है, जब लोगों को उस पर विश्वास हो। यदि विश्वास खत्म हो जाता है, तो कोई भी नियम कानून का पालन कराना किसी भी सरकार और अदालत के बस की बात नहीं होती है। केंद्रीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गंभीरता से विचार करे। स्वतंत्रता के बाद से अभी तक हर बार बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करते थे। निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रति जिम्मेदार होते थे। इसके स्थान पर अब सारा काम केंद्रीय चुनाव आयोग के कंप्यूटर और केंद्रीकृत मशीनी व्यवस्था कर रही है। नोटिस भी वहीं से जारी हो रहे है। ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा, भगवान ही मालिक है।

वाशिंगटन में चीन की चर्चा : जिनपिंग अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं

ली युआन

इन दिनों अमेरिकी अखबारों में इसकी खूब चर्चा है, कि 'एआई के मामले में चीन पर अमेरिका की बढ़त लगभग खत्म हो चुकी है या चीन एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।' जाहिर है, इस हफ्ते जब शी जिनपिंग वाशिंगटन पहुंचेंगे, तो ऐसी चर्चाओं के बारे में जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। शी के नेतृत्व में, चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को विकसित करने में बहुत तरक्की की है। लेकिन, वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था का भी नेतृत्व करते हैं, जो दशकों में अपनी सबसे खराब हालत में है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। चीनी अर्थशास्त्रियों और सरकार के करीबी लोगों ने भी चेतावनी दी है कि सरकार एआई जैसी तकनीक पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, जबकि रोजगार बढ़ाने और पूरी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। देश की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। अगस्त में युवाओं की बेरोजगारी दर 18.9 प्रतिशत पहुंच गई। लोगों की खर्च करने की क्षमता भी कम हुई है। साल की पहली छमाही में घरेलू कारों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत और घरों की बिक्री 14 प्रतिशत घट गई। इससे पहले से जारी आर्थिक सुस्ती और बढ़ गई है। देश में कीमतें लगातार गिरने का दौर भी जारी है। हाल के दिनों में एक सुर में देश के अर्थशास्त्रियों ने चेतावनियां दीं। चीन के केंद्रीय बैंक के पूर्व सलाहकार और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली दाओकुई ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था 'बहुत धीमी' पड़ गई है। तेजी से बढ़ते हाई-टेक सेक्टर पूरी अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं उठा सकते। केंद्रीय बैंक के एक अन्य पूर्व सलाहकार लियू शिजिन ने एक फोरम में सुझाव दिया कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की बुनियादी पेंशन की रकम बढ़ाई जाए, ताकि उनकी क्रयशक्ति को बढ़ाया जा सके। उसी फोरम में, केंद्रीय बैंक के सलाहकार हुआंग हाइझोउ ने कहा कि जो देश कीमतों में गिरावट के चक्र में फंसा हो, वह तकनीकी नवाचार हासिल नहीं कर सकता। एआई के लिए चीनी सरकार कितनी रकम खर्च कर रही है, उसका सही पता लगाना मुश्किल है। स्टैनफोर्ड की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, 2000 से 2023 के बीच सरकारी निवेश फंडों ने एआई कंपनियों में अनुमानित 184 अरब डॉलर का निवेश किया। ब्लूमबर्ग के अनुसार, चीन देशभर में डाटा सेंटर बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब 295 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें सरकारी कंपनियां चलाएंगी। चीन की सत्ताधारी पोलितब्यूरो की नियमित छमाही बैठक से ठीक पहले चीनी अर्थशास्त्रियों की बेबाकी बहुत कुछ बयां करती है। उन्हें बहुत ज्यादा निराशावादी बातें न करने की चेतावनी दी गई थी। जब नेतृत्व आर्थिक नीति में बदलाव करने वाला था, ठीक उससे पहले इन हस्तियों का इतनी साफगोई से बोलना दिखाता है कि वे कितने चिंतित हैं। उनका संदेश साफ था-चीनी अर्थव्यवस्था मुश्किल में है और संसाधनों का एआई-केंद्रित आवंटन आम लोगों की आजीविका और देश के आर्थिक भविष्य के लिए महंगा साबित हो सकता है। नेतृत्व ने उनकी चेतावनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पोलितब्यूरो की बैठक के बाद पार्टी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत मानी। हालांकि, उसने ऐसे प्रोत्साहन उपायों पर ही भरोसा किया, जिनका असर धीरे-धीरे दिखता है। साथ ही, 'एक समझदार नई अर्थव्यवस्था' बनाने का वादा किया। सरकारी मीडिया ने पुरानी परंपरा से हटकर घरेलू विकास का कोई लक्ष्य घोषित नहीं किया। साल के पहले पांच महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और उपकरणों समेत फिक्स्ड-एसेट इन्वेस्टमेंट में 4.1 फीसदी की गिरावट आई। केंद्रीय बैंक के पूर्व सलाहकार ली ने कहा कि चीन के इतिहास में ऐसी गिरावट सिर्फ दो बार देखी गई है-1961 में, जब भयंकर अकाल पड़ा था, और 1967 में, जब सांस्कृतिक क्रांति अपने चरम पर थी। हालांकि, तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद 1989 में भी गिरावट आई थी।

क्यों होती है बेचैनी

आपाधापी व कोलाहल से परिपूर्ण इस युग में उत्तेजना या बेचैनी की शिकायत एक आम बात है। एक अध्ययन के अनुसार 20 से 34 फीसदी लोग इस शिकायत से ग्रस्त हैं।

लक्षण

उत्तेजना या बेचैनी जैसी शिकायत में व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही घबराने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ-पैरों में थरथराहट होती है और पेट में हलचल महसूस होती है। इस रोग का सीधा संबंध हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र से होता है। उत्तेजना से संबंधित दो तरह की बीमारियां प्राय: ज्यादातर लोगों में पाई जाती हैं।

कुछ अनजाने डर

इसे चिकित्सकीय भाषा में 'पैनिक डिसार्डर' भी कहते हैं। इस मर्ज में रोगी बिना किसी कारण के उलझन महसूस करने लगता है। मानो उसकी सांसें रुक जाएंगी और दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे घुटन- सी महसूस होने लगती है। ऐसे रोगी भीड़भाड़ वाली जगह पर नहीं जाते, उन्हें लिफ्ट पर चढ़ने में डर लगता है कि कहीं लिफ्ट न गिर जाए। इसी प्रकार की एक दूसरी समस्या को चिकित्सकीय भाषा में सामान्य उत्तेजना गड़बड़ी (जनरल एग्जाइटी डिसार्डर) कहते हैं। इस रोग में रोगी दिन-भर घबराता रहता है। वह मामूली आहट से भी सहम जाता है। इस वजह से उसे नींद नहीं आती है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है।

उपचार

इस तरह की मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए अब यूएसएफडीए एप्रूव्ड जैसी कई प्रभावशाली दवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। इन दवाओं के सेवन से 12 से 15 सप्ताह के अन्दर रोगी पूर्णत: स्वस्थ हो जाता है, इसके साथ ही रोगी को मनोचिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाता है।

जीभ का स्वाद बिगड़ जाए तो...

- राई - पानी में 10 ग्राम राई को डालकर उबाल लें। इस पानी से प्रतिदिन सुबह-शाम कुल्ला करने से जीभ का स्वाद ठीक हो जाता है।
- नौसादर - 5 ग्राम नौसादर और 5 ग्राम कालीमिर्च को पीसकर इसमें शहद मिलाकर जीभ पर रगड़े तथा लार को बाहर गिरने दें। इससे जीभ की कड़वाहट दूर हो जाती है।
- दालचीनी - जीभ पर कड़वाहट महसूस होने पर दालचीनी या बच को पीसकर और छानकर इस चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से जीभ की कड़वाहट दूर हो जाती है।
- अमलतास - 20 ग्राम अमलतास के गूदे को 250 ग्राम गर्म दूध में मिलाकर कुल्ला करें। इससे अफीम तथा कोकीन के सेवन करने के कारण खराब हुआ जीभ का स्वाद फिर से ठीक हो जाता है।

पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाव

प्रसव के तुरंत बाद की अवधि को पोस्टपार्टम कहते है। इस अवधि के दौरान एक औरत में अवसाद के लक्षण दिखते है और इसीलिए इसे पोस्टपार्टम (प्रसव के पश्चात आने वाला) अवसाद कहा जाता है।

पोस्टपार्टम अवसाद और 'बेबी ब्लू', दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से अलग है, इन दोनों प्रकार के अवसाद के लक्षण भिन्न है। 'बेबी ब्लू' प्रसव पूर्व होने वाली ऐसी अवस्था है, जो सबसे सामान्य है और हर तीन में से एक महिला में यह स्थिति पाई जाती है। प्रसव के बाद कुछ हालतों में शरीर में हुए हार्मोनल परिवर्तन की वजह से ये विकार होता है। प्रसव के बाद नई मां अक्सर भावनात्मक रुप से संवेदनशील हो जाती है, कुछ ही क्षण मे वह खुश हो जाती है और अगले कुछ क्षणो मे दुखी। 'बेबी ब्लू' विकार से और भी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इससे आमतौर पर एक मां की जिम्मेदारी और कार्य मे हस्तक्षेप नही होता और कुछ सप्ताह बाद यह बीमारी खत्म हो जाती है।

पोस्टपार्टम अवसाद एक अलग स्थिति है। यह समस्या प्रसव के पहले, दूसरे या तीसरे महीनो मे किसी भी समय शुरू हो सकती है। इसमे दु:ख और निराशा महसूस होती है या व्यक्ति कभी-कभी खुद को बेकार और दोषी मानता है। नई मां किसी भी कार्य या बात में एकाग्रता या रुचि लेने मे असमर्थ हो जाती है, यहा तक कि बच्चे की जरूरतो को भी पूरा नही कर पाती। कुछ मामलों में बच्चों की जरूरतों को लेकर वो अति व्याकुल भी हो सकती है। वह बहुत चिंताकुल, संवेदनशील बन जाती है और उसके मन मे इस तरह के परेशान करने वाले विचार बार-बार आने से उसको बच्चे के स्वास्थ्य की भी चिंता होने लगती है। ऐसे मे नई मा बार-बार एक ही कार्य करती है, जैसे बच्चे कि बार-बार जांच करती है या फिर लगातार बच्चो के चिकित्सक को फोन करके सवाल पूछती है।

इस विकार के कुछ दुर्लभ मामलो मे, लगभग 1000 मे से 1 मामले में इस विकार वाली महिला (साइकोटिक) मनोरोगी बन जाती है। जिसमे वह वास्तविकता की पहचान करने में असमर्थ होती है। इस स्थिति को कभी-कभी पोस्टपार्टम मनोविकृति कहा जाता है। इस विकार मे मा को मतिभ्रम होता है (जैसे ऐसी आवाजें या महक आना जो वहां नही है) या झूठे भ्रम होना (जैसे उनके बच्चे को शैतान ने पकड़ लिया है) इस प्रकार की हालत मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है और अगर ये विकार एक बार हुआ है तो उसकी दूसरे बच्चे के दौरान होने की संभावना ज्यादा होती है।

पोस्टपार्टम अवसाद 10 में से 1 नई मां में होता है। एक महिला मे प्रसव के बाद ये अवसाद हो सकता है, अगर उसमे निम्नलिखित लक्षण हो-

- अगर उस महिला मे पहले से अवसाद इतिहास है।
- पहली गर्भावस्था के दौरान अवसाद हुआ हो।
- शादीशुदा जिंदगी में परेशानी, मित्रों या परिवार मे सहायक सदस्यो की कमी।
- अपने नए शिशु की देखभाल के लिए कठिनाई, खासकर अगर बच्चे को गंभीर चिकित्सा समस्याएं हैं।
- किशोर माताओं, खासकर यदि वे गरीब आर्थिक ससाधनो वाले परिवारो से है।
- इस तरह के लक्षणो वाली महिलाओं मे पोस्टपार्टम अवसाद कि विशेष रूप से उच्च जोखिम होती है।

आधे से भी कम महिलाएं जिनको पोस्टपार्टम अवसाद होता है, वो उनकी समस्याओं के लिये चिकित्सा कराती है।

कुछ महिलाए इस बात से अनजान होती की उनको पोस्टपार्टम अवसाद है और वह इलाज से ठीक हो सकता है। कुछ महिलाए ऐसा सोचती है की उनको तो एक बच्चा होने के बाद खुश होना चाहिये फिर उनको उदासी क्यों हो रही है, इस तरह के अजीब लक्षणो से उनको शर्मिंदगी होती है और वो किसी से मदद भी नही ले पाती।

पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण

एक महिला जिनको पोस्टपार्टम अवसाद है, उसमे निम्नलिखित लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो सकते हैं-

- टीयर फुलनेस निराश लगना और रोना आना।
- कभी-कभी बच्चे के सुरक्षा को ले के सनकी, मजबूर या बेचैन होना।
- कभी बच्चे को सभालने की जिम्मेदारी को ले के खुद को सक्षम ना समझना।
- खुद को निकम्मा, बेकार या दोषी समझना।
- अतिसंवेदनशील होना या दबाव महसूस होना।
- सभी गतिविधियों मे से रुचि चली जाना या किसी बात पर आनंद होना एक मां होने पर भी आनंद ना होना।
- भूख में परिवर्तन (या तो ज्यादा खाना या आहार में कमी होना)।
- नींद में समस्या (नींद ना लगना, या जल्दी जाग जाना)।
- ऊर्जित दिखना या अत्यंत धीमा होना।
- सामान्य से बहुत चिंतित होना, जो एक बच्चे में सामान्य है।

पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाव

यदि आप गर्भवती है, तो आपके जीवन शैली मे मातृत्व के बाद होने वाले बदलावो की पहले ही तैयारी करके खुद को पोस्टपार्टम अवसाद के जोखिम से बचाने मे सक्षम किया जा सकता है। आप दूसरी माताओं या डॉक्टरो से बात करके नवजात शिशु की देखभाल के बारे मे पूछ सकती है और इसमें कोई संकोच की बात नहीं। अगर आपको नवजात शिशु और आप मे योग्य तालमेल निर्माण होने में समय लगता है तो आपको अपने साथी या डॉक्टर, जिनको आपकी परवाह है, उनसे मदद लेने मे संकोच नही करना चाहिए। अक्सर, जिनमें पोस्टपार्टम अवसाद का एक इतिहास है उनके लिए अवसाद के एण्टीडिप्रेसेंट उपचार के बिना मुकाबला करना मुश्किल होता है। इसलिए प्रसूति के तुरंत बाद डॉक्टर एण्टीडिप्रेसेंट दवा देना शुरू कर सकते है। इसके बारे में आपको पहले ही डॉक्टर से बात करना चाहिए। एक सामान्य नियम के रुप में डॉक्टरो को दवा की राशि गर्भावस्था के दौरान कम से कम निर्धारित करने की कोशिश करते है, लेकिन कभी-कभी अवसाद का जोखिम भ्रूण के जोखिम से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ इन बातो पर चर्चा करे।

चिकित्सा के नए आयाम

एलोपैथी आज दुनिया-भर में सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा प्रणाली है। नित नई औषधि-तत्वों की खोज हो रही है। ज्यादातर दवाओं के गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का रुझान सैकड़ों वर्षों से व्यवहृत और निरापद चिकित्सा पद्धतियों की तरफ देखा जा रहा है।

धब्बेदार अध :पतन

धब्बेदार अध :पतन एक कठिन रोग है और यह एक नंबर के है। एफडीए इलाज को मंजूरी दी गई है। कई तरीकों से काम धीमा करने के लिए, रोक या धब्बेदार अध :पतन के प्रभाव को रिवर्स, कोई भी एक निर्णायक इलाज का परिणाम विश्वसनीय होता है। अध : पतन की जगह लेने के लिए कई परीक्षण हो रहे हैं। इनका उपचार किसी भी हालत के लिए उपयुक्त हो सकता है, अपने नेत्र चिकित्सक के साथ चर्चा करके ठीक तरह से उपचार कर सकते है। इसकी स्थिति सक्रिय होती है। धब्बेदार अध : पतन का व्यवहार शुष्क रहता है। यह इंजेक्शन के माध्यम से प्राप्त होता है।

लाभ

अध : पतन प्रोस्टाग्लैंडीन है, इससे रक्त प्रवाह, रेटिना के बीच रक्त प्रवाह के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कोशिकाओं की रक्षा में मदद करता है।

चमत्कारिक पुष्प औषधि रेस्क्यू रेमेडी

चिकित्सा के क्षेत्र में जो विभिन्न पद्धतियां प्रचलित है, उनमें एक नाम बेच फ्लावर रेमेडीज का भी मौजूद है। इसे रेस्क्यू रेमेडी भी कहते हैं। इस पद्धति की दवाएं चोट लगने की स्थिति में कारगर होती हैं। इनका संक्षिप्त परिचय आइए, जानते हैं।

कैसे हुई खोज

रेस्क्यू रेमेडी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक रहे हैं डॉ. एडवर्ड बेच जो लन्दन में प्रमुख एलोपैथिक डॉक्टर थे। इस चिकित्सा पद्धति से असन्तुष्ट होने से उन्होंने होम्योपैथिक डिग्री प्राप्त की और होम्योपैथिक पद्धति से चिकित्सा कार्य करना शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही वे होम्योपैथिक पद्धति से भी असन्तोष का अनुभव करने लगे और किसी और भी सरल लेकिन सफल चिकित्सा पद्धति की खोज में लग गये। प्रकृति का अध्ययन करते हुए उनका ध्यान फूलों की तरफ गया। उन्होंने विचार किया कि स्वभावत: मनुष्य का मन फूलों की तरह कोमल होता है और मूलत: मनुष्य का अन्तर्मन सौम्य, सरल और भावुक होता है। इसका यह प्राकृतिक रूप मन के जिन छह शत्रुओं से बनता या बिगड़ता है, उनके नाम हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। इन्हीं विकारों के प्रभाव से मनुष्य अपना प्राकृतिक स्वरूप याने स्वाभाविक अवस्था खो देता है। स्वाभाविक अवस्था का होना स्वास्थ्य है और इसे खो देना अस्वास्थ्य है, रोग है। मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था फूलों के समान है और यदि यह अवस्था बिगड़ जावे तो इसे सुधारने के लिये फूलों का प्रयोग किया जा सकता है।

सन 1930 से 1936 तक के 6 वर्ष डॉ. एडवर्ड बेच ने इसी खोज में गुजार दिये और हजारों फूलों पर रिसर्च करने के बाद 38 प्रकार के फूलों को मनुष्य के विकारों को दूर करने में सक्षम पाया और इन 38 प्रकार के फूलों से उन्होंने 38 दवाइयां बनाईं, जो इन्हीं डॉ. के नाम से बेच फ्लावर रेमेडीज के नाम से जानी जाने लगीं। इन 38 दवाओं में से 5 दवाइयां मिलाकर जो 39वीं दवा बनाई गई, उसका नाम रेस्क्यू रेमेडी रखा गया, क्योंकि यह दवा किसी भी खतरनाक और गम्भीर स्थिति से छुटकारा (रेस्क्यू) दिलाने वाली है। इन पांचों दवाइयों की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है-

राकरोज

यह दवा किसी भी दुर्घटना के कारण मन में जो डर या दहशत बैठ जाती है, उसके असर को दूर करती है। जब किसी भी दुर्घटना के कारण मन में इतना डर बैठ जाए कि हर समय वही घटना आंखों के सामने घूमती रहे तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है और मनुष्य शीघ्र ही सामान्य मानसिक अवस्था में आ जाता है।

स्टार ऑफ बेथलहम

यह दवा मानसिक आघात के असर को दूर करती है। कभी-कभी किसी दुर्घटना में शरीर के भीतर अन्दरुनी चोट लगती है, जिसका तत्काल पता नहीं चलता, पर बाद में शरीर में कष्ट पैदा हो जाता है। कई बार ऐसी किसी घटना का मन पर ऐसा गहरा असर होता है कि कई वर्ष गुजर जाने पर भी उसका असर नहीं जा पाता। उस स्थिति में यह दवा पूर्ण सकारात्मक प्रभाव मनुष्य के मन-मस्तिष्क पर करती है।

क्लेमेटिस

जब किसी दुर्घटना के कारण कोई बेहोश हो जाए या अस्वाभाविक रूप से सो जाए, बेसुध हो जाए या कोई ख्याली पुलाव पकाता रहता हो तो यह दवा उसे सामान्य मानसिक अवस्था में ले आती है।

इम्पेशेंस

किसी दुर्घटना के बाद की उत्तेजित अवस्था और चिड़चिड़ेपन की स्थिति इस दवा के सेवन से दूर हो जाती है।

बाल सफेद हो रहे हों तो...

एक चम्मच भर आंवला चूर्ण दो घूंट पानी से सोते समय अंतिम वस्तु के रूप में लें। असमय बाल सफेद होने और चेहरे की कान्ति नष्ट होने पर जादू का सा असर करता है। (साथ ही स्वर को मधुर और शुद्ध बनाता है तथा गले की घर-घराहट भी इससे ठीक हो जाती है।

एक और उपाय है

आंवला चूर्ण का लेप - सूखे आंवलों के चूर्ण को पानी के साथ लेई बनाकर इसका खोपड़ी पर लेप करने तथा पांच दस मिनट बाद केशों को जल से धो लेने से बाल सफेद होने और गिरने बन्द हो जाते है।

आंवला जल से सिर धोएं

25 ग्राम सूखे आंवलों को मोटा कूटकर किए हुए टुकड़ों को 250 ग्राम पानी में रात को भिगो दें। प्रात: फूले हुए आंवलों को कड़े हाथ से मसलकर सारा जल पतले स्वच्छ कपड़े से छान लें। अब इस निथरे हुए जल को केशों की जड़ों में हल्के-हल्के अच्छी तरह मलिए और दस बीस मिनट बाद केशों को सादे पानी से धो डालिए। रूखे बालों को सप्ताह में एक बार और चिकने बालों को सप्ताह में दो बार धोना चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

1980 वोटर लिस्ट विवाद सोनिया पर भाजपा का वार

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अक्सर दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगाती हैं, जबकि खुद लोकतंत्र की चोरी में शामिल रही हैं। भंडारी की यह टिप्पणी राउज़ एवेन्यू में एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, भंडारी ने सवाल उठाया कि गांधी को 1980 में वोट देने की इजाज़त कैसे मिली, जबकि कहा जाता है कि उस समय वह भारत की नागरिक नहीं थीं। उन्होंने पूछा कि 1980 में अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें पूछा गया था कि सोनिया गांधी को किस आधार पर वोट देने की इजाज़त दी गई। क्या उन्होंने दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने की कोशिश की थी?

भाजपा के खिलाफ धर्म बचाने की जंग होगा चुनाव : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके संगी-साथियों की संलिप्तता अब जगजाहिर हो चुकी है और अगला चुनाव भाजपा के खिलाफ धर्म को बचाने की किसी जंग से कम नहीं होगा। यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पहली सतही जांच में ही आँकडा 70 से 50 प्रतिशत आगे बढ़कर 105 प्रतिशत हो गया है। ये बेहद निंदनीय है कि सरकारी देखरेख में 'धर्म धन की चोरी' का इतना अधर्मी कुकृत्य किया गया है। उन्होंने इसी पोस्ट में आगे कहा, भाजपाई और उनके संगी-साथियों की संलिप्तता पूरे अयोध्या में चर्चा का विषय है। जनता का भाजपा पर अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रह गया है। अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, देश व दुनिया में भाजपा की थू-थू हो रही है।

महुआ मोइत्रा ने नदिया घटना पर कोर्ट में लगाई याचिका

कोलकाता। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में अपने कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान उन पर अंडे फेंके जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी याचिका में मोइत्रा ने कहा कि 16 सितंबर की यह घटना तब हुई, जब हाई कोर्ट का पहले से ही एक अंतरिम आदेश मौजूद था। इस आदेश में पुलिस को निर्देश दिया गया था कि जब भी वह सितंबर के आखिर तक अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करें, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई सीरियल लिस्ट के अनुसार की जाएगी। उनके वकील अर्का नाग के अनुसार, नदिया ज़िले के तेहट्टा में हुई घटना के दौरान मोइत्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया; इस घटना में विरोधी पार्टी के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए और आरोप है कि उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके।

यूपी और उत्तराखंड की राज्यसभा सीट पर चुनाव का एलान

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की कुल 12 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सभी सीटों पर 16 अक्तूबर को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। आयोग के अनुसार, इसमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट पर होने वाले नियमित चुनाव शामिल हैं, जहां मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की एक खाली सीट के लिए उपचुनाव भी कराया जाएगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की जाएगी और उम्मीदवार 6 अक्तूबर तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश से कार्यकाल पूरा करने वाले सांसदों में भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी. एल. वर्मा और सीमा द्विवेदी शामिल हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रामजी गौतम का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है।

चार राज्यों में विधान परिषद चुनाव का एलान

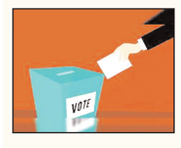

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया है। ये सीटें शिक्षकों और स्नातक लोगों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों के लिए मतदान 23 अक्तूबर को होगी। वहीं, वोटों की गिनती 27 अक्तूबर को की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित चुनाव क्षेत्रों में आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है। चुनाव आयोग के एक बयान के अनुसार, बिहार में विधान परिषद की आठ सीटें 16 नवंबर को खाली हो जाएंगी। कर्नाटक में चार सीटें 11 नवंबर को, महाराष्ट्र में पांच सीटें 6 दिसंबर को और उत्तर प्रदेश में 11 सीटें 6 दिसंबर को खाली हो जाएंगी। जिन राज्यों में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। वहां चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर, 2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 6 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इन चुनावों के लिए वोटिंग 23 अक्तूबर को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 27 अक्तूबर को होगी। संबंधित चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है।

संसद के इतिहास में नया रिकॉर्ड

40 दिन बाद भी मॉनसून सत्र जारी

नईदिल्ली। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के 40 दिन बाद भी मॉनसून सत्र को औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। यह एक असामान्य देरी है, जिससे सरकार के लिए बिना नया सत्र बुलाए कानून लाने की संभावना बनी हुई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक सत्र के सत्रावसान का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचारी ने मीडिया को बताया कि 40 दिनों का यह अंतराल दोनों सदनों के सत्रावसान न होने का एक नया रिकॉर्ड है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में, कार्यवाही स्थगित होने के 28 दिन बाद सदनों का सत्रावसान किया गया था, जब सरकार ज़रूरी कानून पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी। इस देरी से अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार इस दौरान अहम कानून लाने की कोशिश कर सकती है।

जिन कानूनों पर चर्चा हो रही है, उनमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन की एक नई कोशिश भी शामिल है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू किया जा सके। बजट सत्र के दौरान की गई पिछली कोशिश पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण सफल नहीं हो पाई थी। इन प्रस्तावित बदलावों का मकसद दक्षिणी राज्यों की विपक्षी पार्टियों की उन चिंताओं को दूर करना भी है, जिन्हें आबादी के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा में प्रतिनिधित्व घटने की आशंका को लेकर उठाया गया था। सामने आ रहे सुझावों के अनुसार, सरकार सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या में एकसमान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।

आमतौर पर, सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के तीन या चार दिन के भीतर सत्र का सत्रावसान (प्रोरोगेशन) कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, बजट सत्र 18 अप्रैल को समाप्त हुआ था और दो दिन बाद 20 अप्रैल को उसका सत्रावसान कर दिया गया था। संविधान के तहत, सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद का औपचारिक रूप से सत्रावसान किया जाता है। शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होता है और क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाता है।

विधानसभा टिकट के लिए कांग्रेस नई व्यवस्था लागू करेगी

दावेदारी के लिए कांग्रेस फंड में दो लाख रुपये जमा करने होंगे, अपने खाते में 20 लाख रुपये डिपॉजिट दिखाने होंगे

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को लेकर कांग्रेस पार्टी में नई व्यवस्था लागू होने वाली है। पार्टी फंड में दो लाख रुपये जमा करने के बाद ही टिकट की दावेदारी पेश करनी होगी। साथ ही खाते में 20 लाख रुपये डिपॉजिट दिखाने होंगे। ये व्यवस्था दावेदारों की जेबों पर भारी पड़ेगी। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था के बाद जिले में टिकट के दावेदारों की संख्या घट जाएगी।

विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में बदलाव की बयार चल रही है। पहले प्रदेश प्रभारी बदले गए। अविनाश पांडेय की जगह राजेश पाल गौतम को प्रभारी बनाया गया। अब संगठन सृजन का काम चल रहा है। जिला, महानगर समेत सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे।

दूसरी ओर पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए नई व्यवस्था लागू करने वाली है। पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के मुताबिक टिकट की दावेदारी करने के लिए पहले पार्टी फंड में दो लाख रुपये जमा करने होंगे, इसके बाद ही टिकट के लिए दावेदारी कर सकेंगे।

साथ ही अपने खाते में 20 लाख रुपये डिपॉजिट भी दिखाने होंगे। इन सबके बीच विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए दावेदारों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए अभी तक 62 दावेदार सामने आ चुके हैं।

ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 19 लोगों ने दावेदारी पेश की है जबकि सबसे कम पांच दावेदार कांठ सीट पर सामने आए हैं। नगर सीट से दावेदारी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यहां अभी तक 16 दावेदार सामने आ चुके हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन सृजन का काम पूरा होने के बाद नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक टिकट के दावेदारों को प्रोफार्मा दिया जाएगा जिसे भरकर भेजना होगा। इसमें खाते का ब्योरा भी दिखाना होगा। खाते में 20 लाख रुपये दिखाने के बाद दावेदार इसे नहीं निकाल सकेंगे।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा इस बार प्रत्याशियों के चयन के लिए व्यवस्था में पार्टी कुछ बदलाव करने वाली है। टिकट की दावेदारी के लिए पार्टी फंड में दो लाख रुपये जमा करने होंगे। दावेदार को खाते में 20 लाख रुपये जमा भी दिखाना होगा। जिले में अब तक 62 लोग टिकट की दावेदारी कर चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है।

टाटा संस विवाद पर बोले शरद पवार

टाटा ट्रस्ट की विरासत बचाना जरूरी

मुंबई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने टाटा ग्रुप की ट्रस्ट-आधारित विरासत की रक्षा करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्रुप के चैरिटेबल ओनरशिप स्ट्रक्चर और संस्थागत भूमिका को बनाए रखा जाना चाहिए। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में पवार ने कहा कि लीडरशिप को लेकर चल रहे विवाद को बातचीत, उचित प्रक्रिया और टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन का सख्ती से पालन करते हुए सुलझाया जाना चाहिए।

पवार ने टाटा ग्रुप को महाराष्ट्र में गहरी जड़ें रखने वाला एक राष्ट्रीय संस्थान बताया। उन्होंने कहा कि इसकी विरासत इस सिद्धांत पर बनी है कि कारोबार से बनाई गई संपत्ति का इस्तेमाल आखिरकार समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टाटा ट्रस्ट्स की संस्थागत भूमिका और गवर्नेंस के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये ट्रस्ट मिलकर टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, जो इस ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी है।

उनके ये बयान टाटा संस बोर्ड की 17 सितंबर को हुई बैठक के बाद आए हैं, जिसमें डायरेक्टर्स ने एन. चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर फिर से नियुक्त करने के लिए वोट किया था।

चार डायरेक्टर्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इसका विरोध किया। इसके बाद टाटा ट्रस्ट्स ने वोट को अमान्य घोषित कर दिया और तर्क दिया कि ऐसे फैसले के लिए उनके नॉमिनी डायरेक्टर्स की मंजूरी ज़रूरी थी।

प्रियंका ने महिला सुरक्षा पर जताई चिंता

कहा- अगर सड़कों पर सुरक्षा नहीं, तो बड़ी-बड़ी योजनाओं का क्या फायदा?

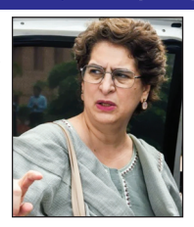

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस नेता और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को दिल्ली और बिहार में महिलाओं के साथ हुए हालिया हमलों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध न केवल बढ़ रहे हैं, बल्कि पहले से कहीं अधिक हिंसक होते जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

वायनाड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं के लिए पहले से ही माहौल असुरक्षित था और अब यह स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा- यह बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए हमेशा से असुरक्षित माहौल रहा है, लेकिन अब महिलाओं के प्रति हिंसा और ज्यादा बर्बर होती जा रही है। मेरा मानना है कि अगर हम सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो बड़ी-बड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की बातें करने का कोई मतलब नहीं रह जाता।

केरल के दौरे पर पहुंचीं कांग्रेस सांसद ने कहा- हर किसी को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बेहद गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, यह सचमुच एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जहां भी राज्य सरकारें हैं और विशेष रूप से केंद्र सरकार, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि वे महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

वायनाड में अपने कार्यक्रमों को लेकर प्रियंका गांधी ने बताया कि यह उनका एक लंबा दौरा है। इस दौरान उनकी कोशिश रहेगी कि वे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों से मुलाकात करें और उनकी समस्याओं को गहराई से समझें, ताकि उन समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय बेटियों ने क्रिकेट में जीता लगातार दूसरा गोल्ड

निशिन (जापान)। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। उनके साथ शेफाली वर्मा ने भी अहम योगदान दिया और 48 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को शुरुआती ओवरों में मजबूती दी और श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। इसके बाद भारत ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे।

भारत की पारी के आखिरी हिस्से में ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 49 रन ठोककर टीम को 200 के पार पहुंचाया। भारत ने 20 ओवर में 216 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 217 रन का लक्ष्य रखा। इस तरह भारत ने फाइनल में श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा किया।

217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत ने मुकाबला 147 रन से जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर श्रीलंका की पारी को संभलने का मौका नहीं दिया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने इससे पहले 2023 हांगझोऊ एशियन गेम्स में भी महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था। इस बार भी टीम ने अपने स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया। श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर में 4 दिन बाद कमजोरी सेंसेक्स 330 अंक गिरकर बंद

नईदिल्ली। निफ्टी 4 दिनों बाद लाल निशान में बंद हुआ। इंडेक्स 85 अंक गिरकर 23329 पर बंद हुआ, जो कारोबारी सेशन में 23489 का हाई बनाया था। सेंसेक्स भी 329.9 अंकों की गिरावट के साथ 74529 पर बंद हुआ। इंडेक्स सेशन के दौरान 75038 का हाई बनाया था। सेंसेक्स में शामिल 21 शेयर लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट बजाज फिनसर्व और ट्रेंट के शेयरों में दर्ज किया गया, जो 1-1 फीसदी से ज्यादा टूट गए। जबकि एटरनल करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड सनी अग्रवाल ने कहा कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बीच उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी शेयरों में निचले स्तरों से सुधार के कारण निफ्टी दिन के निचले स्तर 23,286 से संभला।

प्याज की कीमतों ने बिगाड़ा किचन का बजट

नई दिल्ली। प्याज की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की तुलना में इसकी खुदरा कीमतें करीब दोगुनी से अधिक हो गई हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को प्याज की औसत खुदरा कीमत 54.23 रुपए प्रति किलो रही, जबकि करीब एक महीने पहले यह 40.79 रुपए प्रति किलो थी। थोक बाजार में भी कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला है। 21 सितंबर को प्याज का औसत थोक भाव 4,615.98 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 3,299.85 रुपए प्रति क्विंटल था यानी सालाना आधार पर थोक कीमत में करीब 135 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का असर देश के अलग-अलग शहरों में भी दिखाई दे रहा है।

ऑटो मार्केट में लौटी रौनक जीएसटी कटौती का दिखा असर

नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की मांग में तेजी देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उनकी हिस्सेदारी 10% बढ़ने का अनुमान है। यह महामारी के बाद यह पहली बार है जब नए कार खरीदारों की संख्या में इतनी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाजार में इस बदलाव की एक प्रमुख वजह छोटी और एंट्री-लेवल कारों पर टैक्स में कमी को माना जा रहा है। सरकार ने पिछले साल जीएसटी व्यवस्था में बदलाव करते हुए चार मीटर से छोटी कारों पर टैक्स दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी थी। इसके बाद कम कीमत वाली कारों की मांग में सुधार देखने को मिला है। मारुति सुजुकी के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से अगस्त के बीच कंपनी की कुल बिक्री में पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी बढ़कर 54 फीसदी हो गई।

ओरिएंट केबल्स का का आईपीओ 25 को खुलेगा

नई दिल्ली। नेटवर्किंग केबल और पैसिव नेटवर्किंग उपकरण बनाने वाली कंपनी ओरिएंट केबल्स (इंडिया) लिमिटेड ने 552 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपने आईपीओ का मूल्य दायरा 258 से 272 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने बताया कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 25 सितंबर को बोली के लिए खुलेगा और 29 सितंबर को बंद होगा। इस आईपीओ के तहत 320 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तकों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 232 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) की जा रही है। कंपनी नए शेयरों की बिक्री से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल विस्तार योजनाओं, कर्ज चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

भारत ने खोला वैश्विक बाजारों का नया अध्याय!

किशन सनमुखदास भावनानीं

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ के व्यापार व्यवस्था में बढ़ते शुल्क,बदलती आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण नया अध्याय 20 अक्टूबर 2026 से खुलने जा रहा है। 20 सितंबर 2026 तक भारत नेअपने विभिन्न व्यापारिक साझेदारों के साथ अनेक मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।इनमें श्रीलंका,दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के सदस्य देश ,सिंगापुर, आसियान के दस देश, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के चार देश शामिल हैं; वहीं ब्रिटेन, ओमान,न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ जैसे हालिया समझौते हस्ताक्षर अथवा अंतिम क्रियान्वयन प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इन समझौतों का सकारात्मक प्रभाव भारतीय निर्यातकों को बड़े विदेशी बाजारों में कम शुल्क के साथ प्रवेश, निवेश के नए अवसर,आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता, रोजगार तथा भारतीय विनिर्माण और सेवाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ने के रूप में सामने आया है।भारत -ऑस्ट्रेलिया समझौते के बाद वस्त्र, औषधि रसायन और कृषि सहित कई क्षेत्रों में लाभ दर्ज हुआ है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में जब संरक्षणवाद, शुल्क वृद्धि,आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन और भू- राजनीतिक तनाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, तब एफटीए भारत को अनेक बाजारों से जोड़कर जोखिमों को फैलाने और निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाने में मदद कर सकते हैं।लेकिन इन्हें स्वत: लाभ का सौदा मानना भी उचित नहीं होगा,क्योंकि आयात बढ़ने, घरेलू उद्योग पर

प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, सीमा शुल्क राजस्व में कमी और व्यापार घाटे जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।इसलिए भारत के लिए एफटीए की सफ़लता इस बात पर निर्भर करेगी कि बाजार पहुंच का लाभ वास्तविक निर्यात, निवेश, उत्पादन, रोजगार और तकनीकी क्षमता में कितना बदलता है।

साथियों बात अगर हम भारत -न्यूजीलैंड 20 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला समझौते एफ़टीए की करें तो 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित यह समझौता 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाला है।न्यूजीलैंड की संसद ने 16 सितंबर को इसे लागू करने के लिए आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया,जिसके बाद समझौते के प्रभावी होने का रास्ता और स्पष्ट हुआ।मुक्त व्यापार समझौता मूलत: ऐसा व्यापारिक प्रबंध है,जिसके अंतर्गत दो देश एक-दूसरे के उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम या समाप्त करते हैं और वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा पेशेवरों की आवाजाही के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाते हैं।भारत के लिए इसका महत्व केवल निर्यात बढ़ाने तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भारतीय उद्योग, छोटे कारोबार, किसानों, रोजगार, निवेश, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला व्यापक समझौता है। भारत सरकार के अनुसार, न्यूजीलैंड भारत से आने वाले सभी उत्पादों को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच देगा, जबकि भारत न्यूजीलैंड के लगभग 95 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को समेटने वाले उत्पादों पर शुल्क में कमी अथवा समाप्ति की व्यवस्था कर रहा है।

साथियों, इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता भारतीय निर्यातकों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार का लगभग पूरी तरह खुलना है कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनिरी सामान, औषधि, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य और श्रम-प्रधान उद्योगों को इससे नए अवसर मिल सकते हैं। सीमा शुल्क समाप्त होने से भारतीय उत्पादों की न्यूजीलैंड के बाजार में पहुंच लागत कम हो सकती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे निर्यातकों के लिए शुल्क और परिवहन लागत का प्रभाव अधिक होता है। सरकार ने भी इस समझौते में छोटे और मध्यम उद्यमों तथा महिला उद्यमियों को विशेष महत्व दिए जाने की बात कही है।

माताओं-बहनों का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : साय

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

महतारी वंदन योजना से 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को हर माह मिल रहा आर्थिक संबल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुए। पारंपरिक उल्लास और आत्मीय वातावरण में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने माताओं-बहनों से भेंट कर उन्हें तीज पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं में मातृशक्ति का विशेष स्थान है। माताओं-बहनों का सम्मान, उनकी सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तीज का पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और आत्मीय रिश्तों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का यह पर्व परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना का अवसर है। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रदेश की सभी माताओं-बहनों और उनके परिवारों के सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व भले ही संपन्न हो चुका है, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में माताओं-बहनों के बीच तीज मिलन का अवसर अत्यंत सुखद और आत्मीय है। मुख्यमंत्री निवास में भी तीज के अवसर पर प्रदेशभर से आई बहनों के साथ पर्व का उल्लास साझा करने का अवसर मिला था। हमारी परंपराओं की यही खूबसूरती है कि वे हमें परिवार और समाज से जोड़ती हैं तथा आपसी प्रेम और आत्मीयता को मजबूत करती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में आदिकाल से मातृशक्ति को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हमारे वेदों, पुराणों और

सामाजिक परंपराओं में नारी के सम्मान और उसकी गरिमा का संदेश निहित है। हमारी संस्कृति कहती है - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है।

छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति को देश दुनिया में मिलेगी नई पहचान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी विशिष्ट लोककला, संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहां की सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान और हमारी ताकत है। इसे सहेजने के साथ नई पीढ़ी और देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी तैयार की जा रही है। इससे छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण और शूटिंग की संभावनाओं का विस्तार होगा। स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार तथा प्रतिभा प्रदर्शन के नए अवसर तैयार होंगे और प्रदेश के पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोककला और संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में कलाकारों का अमूल्य योगदान है। हमारे कलाकार अपनी प्रतिभा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सुगंध और यहां की परंपराओं को देश-दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार कलाकारों और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी।

चित्रोत्पला फिल्म सिटी की धीमी रफ्तार पर टूरिज्म बोर्ड सख्त

17 करोड़ की बैंक गारंटी पर क्यों आई आंच?

रायपुर। नवा रायपुर में बन रही चित्रोत्पला फिल्म सिटी परियोजना की धीमी प्रगति पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। परियोजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर बोर्ड ने निर्माण एजेंसी ईगल स्टूडियोज् एंटरटेनमेंट लिमिटेड को औपचारिक नोटिस जारी किया है। संविदात्मक दायित्वों के पालन में कमी को देखते हुए एजेंसी की करीब ?17 करोड़ की बैंक गारंटी को इनवोक यानी जब्त किए जाने की कार्रवाई को लेकर भी नोटिस दिया गया है।

100 एकड़ में विकसित हो रही फिल्म सिटी

चित्रोत्पला फिल्म सिटी नवा रायपुर के माना-तूता क्षेत्र में करीब 100 एकड़ में विकसित की जा रही है। इसे छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण, फिल्म पर्यटन और क्रिएटिव इंडस्ट्री के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। परियोजना में आधुनिक फिल्म स्टूडियो, इनडोर और आउटडोर शूटिंग सुविधाएं, अलग-अलग तरह के स्थायी सेट और प्री एवं पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं विकसित की जानी हैं। फिल्म निर्माण से जुड़ी दूसरी अधोसंरचनाएं भी इसका हिस्सा हैं। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ दूसरे राज्यों के फिल्म निर्माताओं को भी यहां आकर्षित करना है। इसके जरिए स्थानीय कलाकारों और तकनीकी कर्मियों के लिए अवसर बढ़ाने तथा फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजना है।

डिजाइन से लेकर अनुमतियों तक कई कमियां

टूरिज्म बोर्ड की समीक्षा में निर्माण कार्य के पर्याप्त स्तर पर शुरू नहीं होने के साथ परियोजना प्रबंधन और जरूरी अनुमतियों से जुड़ी कमियां भी सामने आईं। इसके बाद एजेंसी को आवश्यक डिजाइन और तकनीकी दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने एजेंसी से संबंधित अनुमतियां हासिल करने, पर्याप्त तकनीकी और पेशेवर अमला तैनात करने तथा साइट पर वास्तविक और सत्यापन योग्य भौतिक प्रगति सुनिश्चित करने को कहा है। नोटिस में साफ किया गया है कि सिर्फ आश्वासन, प्रस्तावित टाइमलाइन या पत्राचार को अनुपालन नहीं माना जाएगा। एजेंसी को जमीन पर वास्तविक और सत्यापन योग्य सुधार दिखाना होगा।

अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे ने कहा कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसी को तय समयसीमा के अनुरूप धरातल पर दिखाई देने वाली ठोस प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं होने पर बैंक गारंटी जब्त करने से लेकर अनुबंध के तहत उपलब्ध अन्य कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड का लक्ष्य परियोजना को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पूरी जवाबदेही के साथ पूरा करना है।

अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे ने कहा कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसी को तय समयसीमा के अनुरूप धरातल पर दिखाई देने वाली ठोस प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं होने पर बैंक गारंटी जब्त करने से लेकर अनुबंध के तहत उपलब्ध अन्य कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड का लक्ष्य परियोजना को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पूरी जवाबदेही के साथ पूरा करना है।

कांग्रेस अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न

रायपुर। संगठन सृजन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा रायपुर संभाग के ब्लाक कांग्रेस अध्यक्षों एवं जिला मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण शिविर सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। समापन अवसर पर सभी ब्लाक अध्यक्षों एवं मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रशस्ती पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रायपुर संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों और जिलों के मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण की शुरुआत ध्वजारोहण और योगा से हुई।

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने पेपर लीक, सरकार के खिलाफ छात्रों के आक्रोश विषय चर्चा की तथा देश के युवाओं में वर्तमान केन्द्र सरकार की नाराजगी को विस्तार में समझाया। सौरभ बाजपेयी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, उत्थान एवं देश के विकास में योगदान पर व्याख्यान दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह-सचिव एवं सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने प्रशिक्षार्थियों से उनके सक्रिय योगदान, सहभागिता, अनुभव और सुझाव को संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। 2028 में छत्तीसगढ़ में और 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार बनाने संकल्पित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के सभी 307 ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया। बस्तर संभाग से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और आज राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में हमने ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा हर जिले से 2 मास्टर ट्रेनरों को भी शामिल किया। हमारा प्रशिक्षण सभी संभागों में तीन दिवसीय आवासीय रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, डॉ. शिव कुमार डहरिया, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, वरिष्ठ नेताओं, प्रशिक्षकों, सभी जिला अध्यक्षों, प्रशिक्षण की टीम को धन्यवाद देता हूं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने आभार प्रदर्शन किया।

प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश तिवारी, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, युगल पांडेय महामंत्री दीपक मिश्रा, विधायक संदीप साहू, विधायक चातुरी नन्द, द्वारिकाधीश यादव, अंबिका मरकाम, महेंद्र बहादुर सिंह, हर्षद मेहता, कुलदीप जुनेजा, लेखराम साहू, डॉ लक्ष्मी ध्रुव, जनक राम वर्मा, चंद्र प्रताप देव, मणि वैष्णव, अशोक चतुर्वेदी, केशव बंटी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भूपेश के काफिले पर हमला भाजपा का अलोकतांत्रिक चरित्र : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल और आसाम के पीसीसी अध्यक्ष गौरव गगोई के काफिले पर नौगांव में कुछ असामाजिक तत्व और भाजपा के लोगों ने पथराव किया। काफिले में चल रही गाड़ी के कांच टूटे है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह घटना असम की भाजपा सरकार के अंदर कांग्रेस के प्रति खौफ को दिखाता है। वहां लोकसभा चुनाव चल रहा है, तथा जनमत कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा। जिससे असम की सरकार डरी हुई है और बौखलाहट में यह घटना हुई। इस घटना की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। यह मांग करती है कि घटना के लिए जो जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा जब-जब चुनाव हारती है तो वह इसी प्रकार के हथकंडे अपनाती है। भाजपा का चरित्र ही अलोकतांत्रिक और फासीवादी है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला करवा कर अपनी प्रति हार को स्वीकार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे उनकी सरकार से राज्य की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही।

जीएसटी सुधार के बाद भी जनता की जेब खाली : कांग्रेस

रायपुर। जीएसटी सुधार, टैक्स कटौती से बचत के दावों के एक साल बीतने पर सरकार से सवाल करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक साल पहले आज ही के दिन 22 सितंबर 2025 को जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा करते हुए आम आदमी

को बड़ी राहत देने का दावा किया था, विज्ञापनों में जमीनी कहीकत सरकारी दावों के विपरीत है। जीएसटी में छूट का वास्तविक फायदा ग्राहक को नहीं मिला, सत्ता प्रायोजित महंगाई और मुनाफाखोरी की भेट चढ़ गयी, आज दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम 22 सितंबर 2025 की तुलना में और ज्यादा है। जीएसटी सुधार के नाम पर इस सरकार ने जनता से छल किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने स्लैब कम करने, जीएसटी दरों में कटौती और सुधार के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इसका लाभ आम उपभोक्ता तक नहीं पहुँचा। कीमतें कम होने के बजाय मुनाफाखोरों की जेबें भर रही हैं। राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग और खाद्य विभाग की ओर से कोई एंटी-प्रोफिटियरिंग निगरानी तंत्र या विशेष फ्लाइंग स्क्वाड गठित नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़ में लक्ष्य का 99 प्रतिशत बोनी पूर्ण

रायपुर। प्रदेश में खेतों में बोनी का कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। 22 सितंबर की स्थिति में राज्य के 48.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का 99 प्रतिशत बोनी पूर्ण हो चुकी है। इस खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश किसानों को सुगमता से मिले खाद-बीज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों को अब तक 13.14 लाख मीट्रिक टन खाद और 4.58 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून के साथ शुरू हुए खेती-किसानी में बोनी का रकबा भी निरंतर बढ़ते जा रहा है।

कृषि विवि में यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवचार, उद्यमिता विकास एवं प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 28 से 30 सितंबर 2026 तक छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कृषि मंडपम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में किया जाएगा। राज्य में उद्यमिता एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले इस यूथ कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से लगभग एक हजार से अधिक नवोन्मेषी युवा उद्यमियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस तीन दिवसीय यूथ कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन 28 सितम्बर को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रामेन डेका करेंगे तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चैधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं एकमात्र बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर-केंद्रित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ भी किया जाएगा। यूथ कॉन्क्लेव के दौरान युवा नेतृत्व वाले उद्यमों और संस्थागत नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली नवाचार एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री बताएं डॉक्टर पैथोलॉजी रिपोर्ट कैसे जांचेंगे?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से पूछा है कि एमबीबीएस डॉक्टर पैथोलॉजी में होने वाले ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट सहित विभिन्न जांचों

की रिपोर्ट की विशेषज्ञता के साथ जांच कैसे करेंगे? पैथोलॉजी जांच और उसकी रिपोर्ट का परीक्षण विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट का कार्य है। ऐसे में बिना आवश्यक विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों से पैथोलॉजी जांच करवाना सीधे तौर पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली विभिन्न जांचों का ठेका एचएलएल को दे दिया है। सरकार ने दावा किया था कि मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी और जांच रिपोर्ट घर तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। दुर्ग जिले के 9 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एचएलएल द्वारा पैथोलॉजी टेस्ट की जिम्मेदारी एमबीबीएस डॉक्टरों को क्यों सौंप दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और एचएलएल जवाब दे? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने एचएलएल के साथ जिला अस्पतालों में 134, सिविल अस्पतालों में 111 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 97 प्रकार की जांचों का ठेका किया है।

कांग्रेस में शामिल होने के एक हफ्ते बाद 150 से ज्यादा कार्यकर्ता आप में लौटे

लोगों के अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई जारी रहेगी

रायपुर। कांग्रेस में शामिल होने के लगभग 10 दिन बाद, पार्टी नेता नूर हसन अली के नेतृत्व में 150 से ज्यादा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अंबिकापुर में पार्टी में वापस लौट आए। कार्यकर्ताओं की वापसी के बाद आयोजित सम्मेलन में सरगुजा के लोगों से जुड़े बुनियादी मुद्दों - जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सड़कें - को ज़ोर-शोर से उठाने और लोगों के बीच सक्रिय रूप से काम करने का संकल्प लिया गया।

राज्य संगठन महासचिव सरदार जसबीर सिंह चावला ने कहा कि

कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की वापसी से संगठन में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गाँव और बूथ स्तर पर आपसी एकजुटता के ज़रिए संगठन को मज़बूत करने का आह्वान किया।आप ने राज्य प्रवक्ता लव कुमार दुबे की गिरफ़्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई; पार्टी बलरामपुर कलेक्टर और एसडीएम के खिलाफफ हाई कोर्ट जाएगी।

रक्तदान, बुक ट्री, क्लॉथ गार्डन, टॉय बैंक एवं देहदान-अंगदान सहित विभिन्न सेवा गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया

लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें : कलेक्टर

रायपुर। कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य करें तथा अभियान के तहत आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों का व्यवस्थित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 23 सितंबर को इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाले सेवा महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यक्रम के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा महाकुंभ को जनभागीदारी का व्यापक स्वरूप देते हुए अधिक से अधिक नागरिकों को सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाए। सेवा महाकुंभ में रक्तदान, बुक ट्री के माध्यम से नई एवं पुरानी पुस्तकों का दान, क्लॉथ गार्डन के माध्यम से नए एवं पुराने कपड़ों का दान, टॉय बैंक के माध्यम से नए एवं पुराने खिलौनों का दान तथा देहदान-अंगदान सहित छह प्रकार की सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

कलेक्टर ने जिलेवासियों से सेवा महाकुंभ में बढ़-चढ़कर भागीदारी कर समाजहित में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

प्रोजेक्ट दधीचि के तहत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं उनकी पत्नी डॉ. सुनीता सिंह देहदान का संकल्प लेंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने कहा कि देहदान एवं अंगदान मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा और नई जिंदगी का संचार करने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। उन्होंने समाज के लोगों को भी इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक होने और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा गतिविधियों में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया।

सेवा महाकुंभ के तहत आयोजित होने वाले रक्तदान अभियान की तैयारियों की भी कलेक्टर ने जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा रक्तदान के लिए किए गए प्रयासों एवं रक्तदाताओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.